

Policy WATCH

Volume XI, Issue 6
June 2022, New Delhi

Special Issue (COVERING ALL THEMES)

In this issue

**Rashtriya Sadbhavana
Yatra, Uttarakhand –
Report**

by Bhuwan Pathak

**Bihar – An overview of
the environmental,
socio-economic and
fiscal situation**

by Vijay Mahajan and
Dr Rakesh Ranjan

**Worrying trends from
Gujarat (compilation
from various sources)**

**Groundwater situation
in Maharashtra** by
Yugandhar Mandavkar

**Focus on India-Russia
talks (compilation from
various sources)**





RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

POLICY WATCH

Volume XI, Issue 6
June 2022, New Delhi

3 **Rashtriya Sadbhavana Yatra, Uttarakhand – Report**

by Bhuwan Pathak

10 **Bihar – An overview of the environmental, socio-economic and fiscal situation**

by Vijay Mahajan and
Dr Rakesh Ranjan

22 **Worrying trends from Gujarat (compilation from various sources)**

26 **Groundwater situation in Maharashtra**

by
Yugandhar Mandavkar

37 **Focus on India-Russia talks (compilation from various sources)**

Editorial

The Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies (RGICS) works on five themes:

1. Constitutional Values and Democratic Institutions
2. Governance and Development
3. Growth with Employment
4. Environment, Natural Resources and Sustainability
5. India's Place in the World.

We bring out the monthly Policy Watch on each of these themes sequentially and every sixth issue is a Special Issue, where we carry articles from each theme. This is a special issue in which we carry one article on each theme.

On the first theme, we carry a report on the recently concluded Rashtriya Sadbhavana Yatra, Uttarakhand, which covered nearly the whole state in a 45 day period. The objective of the Yatra was to spread Sadbhavana (mutuality, sincere fellow-feeling) as it is the very basis of the ideals of Justice, Liberty, Equality and Fraternity cited in the preamble of the Constitution. The article, in Hindi, describes the itinerary of the Workshop, the highlights of discussions with the people during the Yatra and the resolutions in the concluding event.

The second theme - Governance and Development - is explored through an article based on a presentation made in Bihar giving an overview of the environmental, social, economic and fiscal situation of the state. This was done at a workshop titled Bihar Vimarsh in Muzaffarpur, Madhubani, Bettiah, and more to be held in Purnea and Patna.

The third article deals with the theme Growth with Employment. Using recently published Government data from the Annual Survey of Industries, it shows how this is not happening adequately in Gujarat, which leads in the growth of capital investment while Tamilnadu leads in terms of factory employment. We also carry a small item on one particular industrialist from Gujarat and the meteoric rise in his net worth. Even he seems to concede the need for more widespread investment in health, education and skills, and has earmarked Rs 60,000 crore for philanthropic expenditure in these fields.

The next article deals with the theme Environment, Natural Resources and Sustainability. The RGICS has recently concluded a year-long eight state study on groundwater. One of the objectives was to identify and document locally appropriate solutions for regeneration and sustainable management of groundwater. We carry an article which describes the status of groundwater in Maharashtra, and discusses some innovations on groundwater recharge developed by some NGOs with the active participation of local communities.

In the fifth theme, India's Place in the World, we discuss the recent meeting of India's PM with the Russian President and in that context, we reproduce an article by Dr Rajeswari Pillai Rajagopal which asks the question - Why did Putin visit India (in Dec 2021)? The article has special value as the Russian invasion of Ukraine took place soon after that, and explains why India abstained in several UN resolutions condemning the invasion.

We hope the readers find the above articles enjoyable and informative. We would appreciate any feedback.

Vijay Mahajan

Director, Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies

Contents

I Constitutional Values and Democratic Institutions - Rashtriya Sadbhavana Yatra, Uttarakhand – Report by Bhuwan Pathak.....4

1.1 यात्रा का सन्दर्भ एवं उद्देश्य.....	4
1.2 यात्रा के स्थानों की सूची.....	5
1.3 सदभावना यात्रा रिपोर्ट.....	6
1.4 20 जून 2022 – सदभावना यात्रा समापन गोष्ठी, प्रैसक्लब, देहरादून.....	9
1.5 21 जून 2022 – मसीही ध्यान केन्द्र (राजपुर) देहरादून.....	14
1.6 हल्द्वानी से देहरादून तकय सफल रही राष्ट्रीय सदभावना यात्रा.....	16

2 Governance and Development: Bihar – An overview of the environmental, socio-economic and fiscal situation by Vijay Mahajan and Dr Rakesh Ranjan..... 17

2.1 Environmental conditions of Bihar.....	17
2.2 Social conditions of Bihar.....	19
2.3 Economic conditions of Bihar.....	23
2.4 Financial situation of Bihar - State finances.....	26

3 Growth with (out) Employment – Worrying trends from Gujarat (compilation from various sources).....29

3.1 Gujarat's Industrial Clout Keeps Growing.....	29
3.2 And Gautam Adani's Wealth Keeps Growing Too.....	32

4 Environment, Natural Resources and Sustainability - Groundwater Situation in Maharashtra by Yugandhar Mandavkar.....33

4.1 Introduction.....	33
4.2 Groundwater Assessment Methodology.....	36
4.3 Discussion on Current and Future Scenarios.....	41

5 India's Place in the World – Focus on India-Russia Talks (compilation from various sources).....44

5.1 PM Modi and Vladimir Putin hold comprehensive dialogue.....	44
5.2 Why Did Putin Visit India in Dec 2021?.....	45

I Constitutional Values and Democratic Institutions - Rashtriya Sadbhavana Yatra, Uttarakhand

Report by Bhuwan Pathak

I.1 यात्रा का सन्दर्भ एवं उद्देश्य

समाज में बढ़ते हुए भेदभाव, द्वेष, घृणा, यहां तक कि परस्पर अमानवीय व्यवहार का सामना करने के लिए कुछ सामाजिक विचारकों एवं जन कार्यकर्ताओं द्वारा देश की आजादी के 75वें साल के मौके पर एक राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा की परिकल्पना की गई। इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से मई महीने में की गई।

उत्तराखंड में ऐतिहासिक कुली बेगार प्रथा के 100वें वर्ष के मौके पर उत्तराखंड के विभिन्न सामाजिक सस्थानों, लोकतांत्रिक संगठनों, जन आंदोलन समूहों, नागरिक सगठनों और बौद्धिक संस्थाओं द्वारा एक साथ जुड़ कर इस प्रदेश व्यापी यात्रा का आयोजन किया गया।

यात्रा के संचालन एवं प्रबंधन सम्बंधी निर्णयों के लिए एक प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। विभिन्न संगठनों, लोक समूहों एवं सामाजिक संस्थानों ने यात्रा संबंधी जिम्मेदारियां ली।

सात सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूरी यात्रा में शामिल रहने का निर्णय लिया। यह सात हैं सर्वश्री इस्लाम हुसैन, भुवन पाठक, बसंती बहन, साहिब सिंह सजवाल, गोपाल राम, सुन्दर बरोलिया, एवं प्रयाग भट्ट एवं बासंती बहन। इनके अलावा, हर पड़ाव पर बहुत सारे साथी एक से सात दिन तक यात्रा के साथ जुड़े।

यह यात्रा उत्तराखंड की जनता के साथ पर्यावरणीय, लोकतांत्रिक, सामाजिक सौहार्द, आजीविका, एवं पलायन जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर लोक संवाद स्थापित करने की कोशिश है। यात्रा के दौरान विगत 100 सालों के सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं लोकपक्षीय राजनीति के स्थानीय नायकों के जीवन एवं उनके योगदान को भावी पीढ़ी के साथ साझा करने का प्रयास किया गया।

स्थानीय विकास एवं समाज सुधार के उत्तम प्रयासों को श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। साथ ही साथ, युवाओं की आकांक्षाओं एवं शंकाओं के बारे में उनसे संवाद किया गया। अंतरराष्ट्रीय, देशीय, एवं स्थानीय समस्याओं के कारणों एवं परस्पर संबंधों के बारे में समझ बढ़ाई गई।

सद्भावना यात्रा 8 मई से उत्तराखंड के हल्द्वानी नगर से आरंभ हुई। नगरों, कस्बों, एवं गांवों में पैदल तथा इनके बीच बजाज टेम्पो ट्रैवलर मिनीबस द्वारा यह यात्रा कुल चालीस दिन में यह पूरे प्रदेश के हर कोने को छुई तथा पांच दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अलग अलग स्थानों पर पहुंची छ इस यात्रा का समापन समारोह देहरादून में 20 -21 जून 2022 को हुआ जिसमे राज्य भर से लगभग 900 सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े।

1.2 यात्रा के स्थानों की सूची

हल्द्वानी से सुरु होकर 45 दिनों में, 4500 किलोमीटर से अधिक यात्रा, 200 से अधिक सद्भावना सभाओं एवं कार्यक्रमों में लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया एवं उनसे संवाद किया गया।

क्रम	यात्रा स्थल	क्रम	यात्रा स्थल	क्रम	यात्रा स्थल
1	हल्द्वानी	28	चौरा	55	बूढ़ा केदार
2	दिनेशपुर	29	कपकोट भराडी	56	विनक खाल
3	रामनगर	30	बागेश्वर	57	उत्तरकाशी
4	नेनीताल	31	कौसानी अनाशाक्ति आश्रम	58	टिहरी बांध क्षेत्र
5	मल्ला रामगढ़	32	कौसानी लक्ष्मी आश्रम	59	नई टिहरी
6	तल्ला रामगढ़	33	चनोदा	60	चम्बा
7	नधुवाखान	34	अल्मोड़ा	61	जौल गांव
8	छतोला	35	कठपुडिया	62	खाड़ी
9	सतखोल	36	द्वारसाँ	63	गैड गांव जौनपुर
10	मुक्तेश्वर	37	मजखली	64	गरखेत
11	भटेलिया बाजार	38	रानीखेत	65	नोगांव
12	जैती	39	द्वाराहाट	66	चकराता
13	कांडे गांव	40	गैरसैण	67	कालसी
14	दाडुमी गांव	41	नांगनुलाखाल	68	विकासनगर
15	दन्या लक्ष्मी आश्रम	42	चितौली	69	रामपुर
16	दन्या बाजार	43	खंडुआ	70	कोटद्वार
17	पिथौरागढ़	44	दंघाट	71	लैसडोन
18	हुडंती गांव	45	सल्ट खुमाड़	72	सतपुली
19	अस्कोट	46	देवालय सल्ट	73	पोखाल
20	जौलजीवी	47	थलीसैण	74	वीसी (द्वावाटीखाल)
21	मुन्स्यारी	48	पोडी गढ़वाल	75	विनक
22	नाचनी	49	श्रीनगर	76	अठूरवाला
23	मुवानी पीपलतड	50	सिल्यारा आश्रम (बालगंगा घाटी)	77	कोटी
24	बागाड़ नाघर आश्रम	51	बैलैसवर धाम	78	डाईवाला
25	हिमदर्शन कुटी	52	लस्याल गांव	79	दूधली
26	गौखुरी	53	विनकखाल	80	देहरादून (यात्रा समापन)
27	रीमा	54	खवाडा गांव		

यात्रा की योजना-प्रेरणा के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन, नई दिल्ली का आभार। जिन जिन साथियों ने आवास, भोजन व बैठकों का आयोजन किया, उनको धन्यवाद।

हल्द्वानी से उत्तराखंड सद्भावना यात्रा शुरु

हल्द्वानी, संवाददाता। हल्द्वानी से उत्तराखंड सद्भावना यात्रा शुरू हो चुकी है। रविवार को रामपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में हुई गोष्ठी के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर दिनेशपुर के लिए रवाना किया गया। उत्तराखंड में सामाजिक धार्मिक एकता व समन्वय के लिए यह 40 दिवसीय सद्भावना यात्रा आयोजित की जा रही है।

कुली बेगार प्रथा के 100वें एवं देश की आजादी के 75वें साल के मौके पर आयोजित यात्रा में विभिन्न सामाजिक संस्थान, लोकतांत्रिक संगठन, जन आंदोलन समूह, नागरिक संगठन और बौद्धिक संस्थान सहयोगी हैं। प्रक्रार

हल्द्वानी से रविवार को उत्तराखंड सद्भावना यात्रा को दिनेशपुर के लिए रवाना किया गया। स्वर्गीय कुंवर प्रसून के जन्मदिन पर उनकी स्मृति में यह यात्रा शुरू की गई है। गोष्ठी में उत्तराखंड आचार्य कुल के अध्यक्ष विजय शंकर शुक्ला, राज्य आंदोलनकारी पीसी तिवारी, इस्लाम

हुसैन, हुकुम सिंह कुंवर, कैलाश पाण्डेय, अरण्य रंजन, बलवंत बोरा, आनन्द रावत, राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय महाजन, बहादुर सिंह जग्गी, प्रभात ध्यानी आदि रहे।



वैचारिक रूप से यात्रा की योजना बनाने में सहायता के लिए पद्मश्री इतिहासकार डॉ शेखर पाठक, राजीव लोचन साह, पीसी तिवारी, सुरेश भाई, डॉक्टर रमेश पंत, ललित फर्सवाण, हरीश ऐठानी, दर्शना जोशी, सुंदर सिंह मेहरा, लक्ष्मण आर्य व राजीव गांधी फाउंडेशन के विजय महाजन व वरिष्ठ सदभावना फेलो विजय प्रताप का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

यात्रा दल का नेतृत्व उत्तराखंड सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष इस्लाम हुसैन, रीता इस्लाम, गोपाल भाई, सर्वोदय कार्यकर्ता साहब सिंह सजवान, सुंदर सिंह बरोलिया, विजय महाजन, प्रो सोमनाथ घोष, परमानंद भट्ट, जीत सिंह सनवाल, लक्ष्मी सनवाल, प्रयाग भट्ट, रजनीश बिष्ट, रेवा बिष्ट, हिदायत आजमी, मुरारी गोस्वामी, दिनेश लाल, नरेंद्र कुमार, प्रेम बहुखंडी, पीसी तिवारी, किरण आर्य, अमीनुल रहमान, प्रभात उप्रेती, दिनेश कुंजवाल, ललित फर्सवाण, हरीश ऐठानी, डॉक्टर रमेश पंत, सुंदर सिंह मेहरा आदि शामिल रहे।

जिन प्रमुख साथियों ने यात्रा पड़ावों पर सहयोग किया उनमें सर्व श्री डॉक्टर अजय पुंडीर, नैन सिंह डगवाल, रूपेश कुमार, प्रभात ध्यानी, मनमोहन अग्रवाल, राजीव लोचन साह, शेखर पाठक, अनिरुद्ध जडेजा, स्वाति मवाली, रमा बिष्ट, बचे सिंह बिष्ट, दिनेश कुंजवाल, अनिला पंत, चंद्रा पंत, महेश पुनेठा, महेंद्र रावत, भगवान रावत, राजेश उप्रेती, रेनू ठाकुर, जगत मतोलिया, नरेश द्विवेदी, अनिल कार्ले, कमलदीप रावत।



1.3 सदभावना यात्रा रिपोर्ट

सदभावना भाईचारा के संदेश के साथ राष्ट्रीय सदभावना यात्रा 8 मई 2022 को हल्द्वानी से प्रारंभ हुई। 8 मई कुंवर प्रसून जी की जयंती होती है। हल्द्वानी से शुरू होकर 20 जून 2022 को यात्रा का समापन देहरादून में हुआ, इस बीच यात्रा में लगभग 4500 किलोमीटर की सड़कें नापी 40 राते उत्तराखंड के अलग-अलग स्थानों पर बिताई, लगभग 200 से अधिक बैठके, नुक्कड़ सभाएं, संस्कृतिक रैलियों, जनसभाओं द्वारा लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया। यात्रा की शुरुआत संदेश यात्रा के तौर पर हुई, लेकिन धीरे-धीरे यह यात्रा शोध व अध्ययन यात्रा में बदल गई, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे सामने उत्तराखंडी जनजीवन के नए अध्याय खुलते चले गए।

कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने व आजादी के 75वें साल में अपने लोकनायकों को हम याद करते रहे। पिछले 100 सालों में पहले राष्ट्रीय आंदोलन फिर आजाद भारत के निर्माण में जिन लोकनायकों ने अपना जीवन खपा दिया उनके कार्यक्षेत्र व जन्मभूमि से भी यह यात्रा गुजरी, कुली बेगार आंदोलन की भूमि बागेश्वर जहाँ गांधी जी का आना एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई उनके आने के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा रचनात्मक आंदोलन व कार्यों की निरंतरता आज भी उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देती है।

1970-80 के दशक तक विभिन्न सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक आंदोलनों तथा कामों में अग्रणीय दिखाई देने वाला गांधीवादी आंदोलन अब कमजोर दिखाई देने लगा है। खादी ग्रामोद्योग का काम करने वाली रचनात्मक संस्थाएं भी नई बाजार व्यवस्था का शिकार हुई हैं। इसके बावजूद सर्वोदय व भूदान आंदोलन में भागीदारी करने वाली पीढ़ियां तथा उनकी स्मृति अभी शेष है, लोग उन दिनों तथा तब के माहौल को भावुकता से याद करते मिलेद्य 1950 और 60 के दशक की बालिका शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण के काम में लगी महिला समाज कर्मियों से मिलना अभूतपूर्व थाद्य विमला बहुगुणा, शशी प्रभा रावत, शोभा बहन, दिशा बहन व राधा द्दीप्ती से मिलना, बात करना अविस्मरणीय रहेगा। खाड़ी में स्वर्गीय दुलारी बहन से मिलना तो वरदान जैसा था क्योंकि हमारी मुलाकात के आठवें दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।

इसी भांति चिपको आंदोलन के विभिन्न साथियों व कार्यकर्ताओं की यात्रा में बढ़-चढ़कर भागीदारी ने यात्रा को जीवंत बनाया। विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलन तथा कार्यों का प्रभाव तथा जानकारी एकदम हासिये में दिखाई दी। 'नशा नहीं रोजगार दो' आंदोलन, कनकटा बैल, 70 व 80 के दशक का छात्र आंदोलन धीरे-धीरे राजनीतिक शोरगुल में भुलाया जाने लगा है। अस्कोट-आराकोट यात्रा को याद करने वाले लोगों से मुलाकात हुई। आधुनिक विकास के प्रति लालायित समाज प्रकृति व पर्यावरणीय नुकसान को लेकर चुप्पी साधे हैं। टिहरी के पराभव ने आधुनिक विकास के जीत की घोषणा कर दी है। पर्यावरणीय सवालों का आधुनिक मुहावरा हमारे वनवासी समाज की मूल अवधारणाओं तथा भाषा से मेल नहीं खाता दिखा।

पहाड़ों में विशालकाय होटल निर्माण, जमीनों की खरीद-फरोख्त लगातार बढ़ रही है। स्थानीय समाज इस सवाल पर दो हिस्सों में बटा दिखता है। सख्त भू-कानून की मांग भी सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों से आ रही है। प्राकृतिक संसाधनों को लेकर संघर्ष भी यहां तीखा होता जा रहा है। यह कमोबेश पूरे उत्तराखंड में सबसे बेहतर आबोहवा वाली ऊंची जगह पर दिखाई दे रहा है।

पूरे पहाड़ में लगातार कूड़े के पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं। प्लास्टिक कचरा उत्तराखंड के हर कोने तक पहुंच रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, गांव के रास्तों के साथ-साथ कचरा भी चलता रहता है, हर नगर-निगम, नगर-पालिका व नगर-पंचायत में सुंदर गीत गाते हुए कचरा गाड़ी चलती रहती है, लेकिन कचरे का ढेर बिल्कुल शहर के नजदीक बढ़ता जा रहा है। इस कचरे से निपटने में सरकारें, नगर- निकाय व समाज विफल दिखता है।

उत्तराखंड में लगातार नए कस्बे बढ़ते व फैलते जा रहे हैं पिछले दो-तीन दशकों में सैकड़ों नए कस्बे तेजी से फले फूले हैं। यहां नई बाजार नीति, स्कूल, बैंक सुविधाएं, बारातघर, निजी अस्पताल खुले हैं गांव में रहने वाली बड़ी आबादी गांव से यहां स्थापित हो गई है। इन कस्बों का अनियोजित निर्माण व अशुरक्षित भविष्य के लिए खतरा है। 2-3 दसको पहले तक पहाड़ों का उत्पादक मानव श्रम कस्बों व शहरों में आकर लगातार अनउत्पादक श्रम में तब्दील हो रहा है।

पहाड़ के गांव में होने वाला लघु-निर्माण (सार्वजनिक निर्माण) जैसे पंचायतघर, यात्री विश्राम गृह, सार्वजनिक शौचालय, पटवारी चौकी, एनम सेंटर, प्राथमिक विद्यालय, लघु नैहरे, व पुल बहुत ही घटिया स्तर के निर्माण सामग्री से बनाए जा रहे हैं। इन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर ना हो तो चर्चा हो रही है ना इसका विरोध हो रहा है इस भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग सब हमारे आसपास के लोग हैं। एक आश्चर्यजनक चुप्पी इस भ्रष्टाचार को लेकर हमें दिखती है।

राज्य निर्माण के 22 साल पूरे होने के पश्चात भी सार्वजनिक सुविधाओं की आपूर्ति या बहाली बहुत निराशाजनक है, लोग यह कहते मिलते हैं कि इससे बेहतर तो उत्तर प्रदेश में थे, सरकारी विभागों की लापरवाही चरम पर है। कृषि विभाग व उद्यान विभाग जिसकी नीतियां लागू कर रही हैं उससे हमारी परंपरागत कृषि व उद्यान को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। लगातार बढ़ता बंजर, सरकती नदियां, नाले, घोर, जलते जंगल फैलता चीड़ भी हमारी पर्यावरणीय महामारी की ओर इशारा कर रहा है। लगभग सभी इलाकों में लोगों की स्वीकारोक्ति है कि पेयजल व सिंचाई योजनाओं ने हमारी छोटी नदियों, गधरो व तालों को लगभग समाप्त कर दिया है। नदियों में मिलने वाली मछलियां तथा अन्य जलीय जीव लगातार घटते जा रहे हैं।

इन सब निराशाओं के साथ-साथ बेरोजगारी व पलायन हमारी समस्त संभावनाओं के द्वारा बंद कर दे रहे हैं। जिन युवाओं को पहाड़ के जैसे श्रमकारी जीवन व सरल व सुगम बनाना था वो युवा रोजगार खासकर नौकरियों के लिए पहाड़ से लगातार मैदानों या महानगरों की ओर जा रहे हैं।

धार्मिक व जातिगत भेदभाव भी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। जिन गाँवों व लोगों ने किसी अन्य धार्मिक समूह को देखा तक नहीं है, वह भी टेलीविजन व फोन से अपनी राय बना रहे हैं। जातिगत भेदभाव शहरों बाजारों व कस्बों में कम हुआ है, छुआछूत घटा है, लेकिन गांव में भेदभाव जस का तस बना हुआ है। कई बार हिंसक तक हो जा रहा है।

इन सब निराशाओं के बावजूद कई आशा जनक बातें भी इस यात्रा के दौरान देखने को मिली, पहाड़ की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित हो रहे हैं। रोजगार के नई पहल कर रहे हैं, युवाओं ने कम निवेश में किए जा सकने वाले कारोबार शुरू किए हैं। बालिका शिक्षा बेहतर दिखाई देती है, सरकारी स्कूल उनके शिक्षक नवाचार व रचनात्मकता के साथ लगातार बेहतर होते जा रहे, सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

इन तमाम और ढेर सारे अन्य अनुभवों संवादों के साथ यहां यात्रा समाप्त हुई। 20-21 जून को देहरादून में विभिन्न जन संगठनों, संस्थाओं, आंदोलन समूहों ने मिलकर आगे के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की।

यात्रा के दौरान चर्चा किए गये मुख्य बिन्दु:

सामाजिक मुद्दे	आर्थिक मुद्दे	पर्यावरणीय मुद्दे
धार्मिक एवं जातीय दुर्भावना का फैलाव	स्थानीय अर्थव्यवस्था का कमजोर होना	जल, जंगल, जमीन के उपर स्थानीय लोगों का अधिकार नहीं रहा
लोक चेतना जागरण का अभाव	आर्थिक विषमता में बढ़ाव	ग्लेसियर, नदियां, धारे, नौले सब सूख रहे हैं
उच्च शिक्षा के अवसरों में बृद्धि परन्तु में गुणवत्ता में गिरावट	आजिविका के अभाव के कारण बेरोजगारी	बांधों और विकास परियोजनाओं के कारण, नदियों का प्रवाह न्यूनतम हो गया
युवाओं के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण का अभाव	महंगाई के कारण कमजोर वर्गों में अधिक भार	वन पंचायत प्रणाली होने के बावजूद स्थानीय लोगों को लाभ नहीं
स्वास्थ्य एवं सफाई - चिकित्सा एवं नागर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी	कृषि उत्पादन एवं लाभ की कमी	जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण गर्मी, सर्दी एवं वर्षा
पुरुषों में शराब की लत	उत्पादित माल के लिये बाजार की कमी	प्राकृतिक आपदा - भूस्खलन, अचानक बाढ़
महिलाओं के उपर घरेलू काम का बोझ एवं आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं	आय के स्थानीय स्रोतों की कमी	भूकंप आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ी है
पलायन एवं विस्थापन	सरकारी योजनाएं - नरेगा इत्यादि से सीमित लाभ	प्लास्टिक कचरे की बढ़ोत्तरी
आपसी संवाद और सामुहिक कार्यों की परंपरा में गिरावट	स्थानीय संसाधनों का दोहन परन्तु स्थानीय लाभ नहीं	अनियंत्रित पर्यटन के कारण, प्राकृतिक सौन्दर्य का हास

यात्रा के दौरान, हमने उन तमाम जन नायकों/लोक नायकों को इस महत्वपूर्ण अवसर पर स्मरण किया जिन्होंने पछले 100 वर्षों के दौरान विविध भाषाई, भौगोलिक, सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों व मान्यताओं वाले समाज को एकजुट किया। इसके अलावा जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनों व उसके पश्चात अपना जीवन समाज की बेहतरी के लिये न्योछावर किया। यात्रा के दौरान अलग-अलग स्थानों में लगभग 800 सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं, व्यवसायिक एवं बुद्धिजीवी संगठनों के साथियों ने कार्यक्रम के आयोजन में अत्यधिक सहयोग दिया, उनके प्रति आभार।



1.4 २० जून २०२२ – सदभावना यात्रा समापन गोष्ठी, प्रैस क्लब, देहरादून

प्रातः 10 बजे सदभावना यात्रा दल व प्रदेश भर से आये साथी गांधी पार्क देहरादून में एकत्र हुये, वहाँ से जनगीतों तथा नारों के साथ समस्त यात्रा दल प्रैस क्लब देहरादून पहुँचा। वहाँ पहुँचकर यह एक गोष्ठी में बदल गया।

जनगीतों के साथ दिन के प्रथम सत्र की शुरुआत हुई। पहले सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन शाह व वरिष्ठ गांधीवादी विचारक बीजू नेगी ने की तथा सभा का संचालन वरिष्ठ आंदोलनकारी तथा महिला मंच की संयोजिका कमला पंत ने किया।

इसके पश्चात् यात्रा दल में शामिल रहे उत्तराखण्ड सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष इस्लाम हुसैन, गोपाल भाई व भुवन पाठक ने अपने यात्रा अनुभवों को साझा किया।

8 मई 2022 को हल्दानी से शुरू होकर तकरीबन 4500 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के पश्चात् 15 जून को यात्रा देहरादून पहुँची। 15 जून तक लगातार देहरादून शहर के आसपास सदभावना कार्यक्रम आयोजित होते रहे, जिनमें बैठकों के अलावा खाराखेत की यात्रा तथा देहरादून में अलगदूअलग स्थानों पर सदभावना दौड़ का आयोजन किया गया। इन समस्त कार्यक्रमों में लगभग 200 से अधिक बैठकें, गोष्ठियाँ, जनसभाएँ, नुक्कड़ सभाएँ, सांस्कृतिक रैलियों का आयोजन किया गया। सदभावना यात्रा के दौरान प्रत्यक्ष रूप से 10000 लोगों से संवाद स्थापित किया गया तथा 800 से अधिक साथियों ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता की।

जिन भी साथियों ने आवास, भोजन व बैठकों का आयोजन किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया। यात्रा की योजना-प्रेरणा के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन, नई दिल्ली का आभार व्यक्त किया गया, जिनकी सहायता के बिना इस महत्वपूर्ण यात्रा का संचालन संभव नहीं था।

वैचारिक रूप से यात्रा की योजना बनाने में सहायता के लिए पद्मश्री इतिहासकार डॉ शोखर पाठक, राजीव लोचन साह, पीसी तिवारी, सुरेश भाई, डॉक्टर रमेश पंत, ललित फर्स्वाण, हरीश ऐठानी, दर्शना जोशी, सुंदर सिंह मेहरा, लक्ष्मण आर्य व राजीव गांधी फाउंडेशन के विजय महाजन व वरिष्ठ सदभावना फेलो विजय प्रताप का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

यात्रा दल का नेतृत्व उत्तराखंड सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष इस्लाम हुसैन, रीता इस्लाम, गोपाल भाई, सर्वोदय कार्यकर्ता साहब सिंह सजवान, सुंदर सिंह बरोलिया, विजय महाजन, प्रो सोमनाथ घोष, परमानंद भट्ट, जीत सिंह सनवाल, लक्ष्मी सनवाल, प्रयाग भट्ट, रजनीश बिष्ट, रेवा बिष्ट, हिदायत आजमी, मुरारी गोस्वामी, दिनेश लाल, नरेंद्र कुमार, प्रेम बहुखंडी, पीसी तिवारी, किरण आर्य, अमीनुल रहमान, प्रभात उप्रेती, दिनेश कुंजवाल, ललित फर्स्वाण, हरीश ऐठानी, डॉक्टर रमेश पंत, सुंदर सिंह मेहरा आदि शामिल रहे।

जिन प्रमुख साथियों ने यात्रा पड़ावों पर सहयोग किया उनमें सर्व श्री डॉक्टर अजय पुंडीर, नैन सिंह डगवाल, रूपेश कुमार, प्रभात ध्यानी, मनमोहन अग्रवाल, राजीव लोचन साह, शोखर पाठक, अनिरुद्ध जडेजा, स्वाति मवाली, रमा बिष्ट, बचे सिंह बिष्ट, दिनेश कुंजवाल, अनिला पंत, चंद्रा पंत, महेश पुनेठा, महेंद्र रावत, भगवान रावत, राजेश उप्रेती, रेनू ठाकुर, जगत मतोलिया, नरेश द्विवेदी, अनिल कार्ले, कमलदीप रावत।

चर्चा की शुरुआत यात्रा दल का नेतृत्व कर रहे इस्लाम हुसैन ने की। उन्होंने कहा कि तमाम तरह की शंकाओं व डर के बावजूद यात्रा सफल रही। यात्रा के दौरान हमने यात्रा के उद्देश्य को बेहिचक निडरता से लोगों के सामने रखा। भाईचारा व कौमी एकता के गीत व नारे लगाये।



लोगों ने इस पहल का खुलकर स्वागत किया। उसमें शामिल हुये, गोपाल भाई ने कहा कि यात्रा के दौरान एक बात समझ में आई कि समाज का खुद से अपनी समस्याओं के समाधान की पहलें कमजोर होती जा रही है। खासकर जिस भी काम का जिम्मा राष्ट्र राज्य ने लिया उसको लेकर एक खास तरह की बैचेनी और उदासीनता समाज में दिखाई देती है। जिन त्योहारों व उत्सवों को हम हर्ष व खुशी व्यक्त करने के लिए मनाते थे, अब वो त्योहार गुस्सा और घृणा व्यक्त करने के माध्यम बन गये हैं। और जो धर्म राजसत्ता से टकराकर पैदा हुये थे वही धर्म अब राजसत्ता की चाटुकारिता में व्यस्त हो गये हैं।

यात्रा दल संयोजक भुवन पाठक ने उन समस्याओं की ओर इशारा किया जो आज भी समाज में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि समाज में आपसी संवाद व संपर्क घटा है। धर्म—जाति, भौगोलिक बोली—भाषा के आधार पर छोटे—छोटे समूह बन गये हैं। जिनका आपसी सम्पर्क व संवाद लगातार घट रहा है। हम बिना एक दूसरे का सच जाने ही विरोध करने लगे हैं। राज्य निर्माण के 22 वर्षों बाद भी प्रदेश के गाँव बदहाल स्थिति में हैं तथा गाँवों को लेकर सटीक व व्यवहारिक योजनाओं का अभाव है।

चर्चा में पीसी तिवारी ने यात्रा को प्रांसगिक बताते हुए, देश में जिस तरह से हिंसा व नफरत को लेकर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, के खिलाफ उत्तराखंड में सबको एकजुटता से आगे बढ़ने पर बल दिया। पी सी तिवारी ने कहा जातीय— धर्म सद्भाव को बनाये रखने के लिये दीर्घकालीन योजनाओं पर काम किया जाना चाहिये। अगले वक्ता के तौर पर विजय महाजन ने यात्रा के मूल विचार व राजीव गांधी फाउंडेशन की भूमिका पर बात की तथा सद्भावना से आगे बढ़कर समाधान तक कैसे पहुँचे दृ इस सवाल को महत्वपूर्ण बताया। विजय प्रताप ने सांप्रदायिकता के बढ़ते जहर को रोकने के लिये सामूहिक रणनीति व छोटे—छोटे सार्थक प्रयासों पर बल दिया। अध्यक्षीय भाषण में बीजू नेगी व राजीव लोचन शाह जी ने पुनरु यात्रा के अनुभवों को भविष्य की रणनीति के लिये महत्वपूर्ण बताया तथा इस क्रम को लगातार जारी रखने की अनिवार्यता पर बल दिया।

चर्चा में पीसी तिवारी ने यात्रा को प्रांसगिक बताते हुए, देश में जिस तरह से हिंसा व नफरत को लेकर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, के खिलाफ उत्तराखंड में सबको एकजुटता से आगे बढ़ने पर बल दिया। पी सी तिवारी ने कहा जातीय— धर्म सद्भाव को बनाये रखने के लिये दीर्घकालीन योजनाओं पर काम किया जाना चाहिये। अगले वक्ता के तौर पर विजय महाजन ने यात्रा के मूल विचार व राजीव गांधी फाउंडेशन की भूमिका पर बात की तथा सद्भावना से आगे बढ़कर समाधान तक कैसे पहुँचे दृ इस सवाल को महत्वपूर्ण बताया। विजय प्रताप ने सांप्रदायिकता के बढ़ते जहर को रोकने के लिये सामूहिक रणनीति व छोटे—छोटे सार्थक प्रयासों पर बल दिया। अध्यक्षीय भाषण में बीजू नेगी व राजीव लोचन शाह जी ने पुनरु यात्रा के अनुभवों को भविष्य की रणनीति के लिये महत्वपूर्ण बताया तथा इस क्रम को लगातार जारी रखने की अनिवार्यता पर बल दिया।

द्वितीय सत्र

भोजन के पश्चात् द्वितीय सत्र प्रारंभ हुआ जिसमें सभी साथियों ने अपना परिचय तथा वैचारिक पक्ष रखा। इस सत्र कि अध्यक्षता कमला पंत एवं पीसी तिवारी ने की तथा संचालन भुवन पाठक ने किया। चर्चा की शुरुआत में पीसी तिवारी ने आज के माहौल में सक्षम राजनैतिक हस्तक्षेप कि आवश्यकता पर बल दिया।

विजय प्रताप ने राष्ट्रीय माहौल पर बात करते हुये कहा कि समाज में विभिन्न धर्मों— जाति समूहों के बीच आपसी संवाद व संबंधों पर चौतरफा हमला हो रहा है। आज के माहौल में आपसी संवाद लगातार बना रहे यह आवश्यक है।

रामनगर से आए साथी प्रभात ध्यानी ने सांप्रदायिकता के खिलाफ सशक्त राजनैतिक हस्तक्षेप की वकालत की। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए समस्त वैचारिक संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा, गांधीवादी विचार व संगठनों की जिम्मेदारी अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।

टिहरी से आए देवेन्द्र बहुगुणा ने सर्वोदय विचार व आंदोलन को पुनः संगठित करने पर जोर दिया तथा कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तथा उसके बाद मीरा बहन व सरला बहन की वैचारिक व सांगठनिक परंपरा का एकजुट होना चाहिए। देहरादून के साथी प्रेम बहुखण्डी ने उत्तराखंड खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए नये विकास के माडल पर सोचने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा नेहरू माडल पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया।

सल्ट से आए साथी शंकर ने ग्रामीण समुदाय में व्याप्त निराशा व हताशा को तोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण समाज जिसमें महिलाओं की अधिकता है। उनके साथ संवाद किया जाना चाहिए। उनकी आजीविका को सशक्त बनाना चाहिए।

राजीव लोचन शाह जी ने आजादी के 75 वर्षों बाद के पहाड़ की पीड़ा को संबोधित किया। पिछले 8-10 सालों में माहौल इतना बदल गया है कि चारों ओर भय-निराशा व मानसिक गुलामी दिखाई देती है। ऐसे माहौल में जब कहीं भी आशा व उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था तब सद्भावना यात्रा ने संभावना के नये द्वार खोले हैं।

देहरादून के साथी त्रिलोचन भट्ट ने सद्भावना यात्रा के बाद की संभावनाओं व चुनौतियों पर प्रकाश डाला। इस सत्र के अध्यक्षीय भाषण में कमला पंत जी ने सद्भावना यात्रा जैसे कार्यक्रमों की प्रासंगिकता का महत्वपूर्ण माना उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जिला व विकास खंड स्तर पर सद्भावना समितियों का गठन किया जाना चाहिए। ताकि यात्रा के दौरान उत्साहित साथियों को जोड़ा जा सके। उन्होंने देहरादून में चल रहे शांति दल के काम को भी सभा में प्रस्तुत किया। अंत में आज की बैठक के समापन की घोषणा की।



प्रेस नोट – 20 जून 2022

हम सद्भावना के साथी पिछले 45 दिनों से उत्तराखंड में 4500 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात आज यहां एकत्र हुए हैं। इन 45 दिनों में 200 से अधिक कार्यक्रम तथा विभिन्न स्थानों पर रात्रि प्रवास के दौरान तकरीबन 10,000 लोगों से हमारा संपर्क हुआ, इस दौरान लगभग 800 से अधिक साथियों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर यात्रा में सहयोग किया, यात्रा के दौरान आयोजित अधिकांश कार्यक्रमों में सभा संबंधी संसाधनों जैसे कुर्सियां, मेज, माइक सहित जलपान की व्यवस्था स्थानीय आयोजक साथियों के द्वारा की गई, यात्रा दल के भोजन व आवास का इंतजाम भी अधिकांश स्थानों पर स्थानीय सहयोगियों द्वारा किया गया।

8 मई को स्वर्गीय कुंवर प्रसून के जन्मदिन के अवसर पर हल्द्वानी से शुरू होकर यात्रा उधम सिंह नगर की तराई से होते हुए पहाड़ों की मुख्य घाटियों, ऊंचे पहाड़ों, सुंदर जंगलों, नदियों, गाड़ों, गावों, बाजारों, नगरों को पार करते हुए 40 दिन बाद देहरादून पहुंची, विगत 5 दिनों में देहरादून नगर में आसपास विभिन्न संगठनों, साथियों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया।

इस यात्रा के दौरान हम सद्भावना के साथियों को अभूतपूर्व अनुभवों से गुजरने का मौका मिला, कुली बेगार आंदोलन के 100 सालों, आजादी के 75 सालों तथा अलग राज्य के 22 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए या जो स्थितियां बनी हैं उनको जानने समझने का मौका मिला, जिन भी लोगों से हम मिले शुरुआती संकोच वह झिझक के बाद बुजुर्गों दृ महिलाओं, युवाओं ने अपनी राय वह बात खुलकर सामने रखी। इस यात्रा के दौरान जो भी बातें हमारे सामने आईं उनको संसीदा रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।

1. राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सद्भाव भाईचारा व आपसी प्रेम के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी अभिव्यक्ति उतनी सशक्त नहीं दिखाई दी, लोगों ने आज के माहौल को शांति व बेहतर मानवीय विकास के प्रतिकूल माना।
2. हमारे समाज में विभिन्न धार्मिक व जातीय समूहों के बीच आपसी संवाद के अवसर लगातार कम हो रहे हैं। पलायन व मिलकर साथ में काम करने के अवसर घटने के कारण आपसी संवाद – बातचीत व सहकार लगाना कम हो रहा, इससे आसानी से एक दूसरे के बारे में गलत जानकारियों को सच मान लिया जा रहा है।
3. जातियों के बीच भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर जातीय आधार पर भेद-भाव घटा है।
4. समस्त यात्रा के दौरान यह बात सामने आई कि हम देवभूमि के साथ-साथ वनभूमि के लोग हैं हमारी खेती दृपशुपालन, खान-पान, फल फूल, दवा, दारू दैनिक उपयोग की बहुत सी वस्तुएं, आबोहवा, देवी देवता सब वनों से आते हैं।
5. आर्थिक तौर पर पहाड़ वह मैदान दोनों जगह गरीबी – पलायन और बेकारी लगातार बढ़ रही है।
6. पहाड़ में लगातार नया बंजर फैल रहा है।
7. पहाड़ प्लास्टिक तथा अन्य तरह के कचरे के ढेर में बदलता जा रहा है। ठोस कूड़ा निस्तारण की तकनीक व योजनाओं का अभाव है।
8. अनियंत्रित व नियोजित भवन निर्माण घातक श्रेणी तक असुरक्षित होता जा रहा है, नए बाजारों, कस्बों, नगरों के भौतिक विकास ने नदियों, खालों, गंधेरो को अपनी चपेट में ले लिया, जो लगातार प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहा है।
9. राज्य में सार्वजनिक निर्माण जैसे पंचायत घर, यात्री विश्राम गृह, सार्वजनिक शौचालय, पटवारी चौकी, एएनएम सेंटर, प्राथमिक विद्यालय घटिया निर्माण व भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे हैं और इस सवाल पर सार्वजनिक बहस या कार्यवाही नहीं हो रही है।
10. लगातार सिकुड़ती खेती के कारण जहां एक ओर भोजन के लिए निर्भरता बाजार पर बढ़ रही है वहीं खानपान में स्थानीयता व मौसम संबंधी भोजन कि प्रचुरता घट रही है।
11. बेहतर वन्यता व जैव विविधता वाले क्षेत्र लगातार पर्यटन व्यवसाय के लिए बेचेखरीदे जा रहे हैं, विशालकाय होटल निर्माण तथा जनसंख्या दबाव के चलते प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव उसके लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा है।
12. राज्य के भीतर पलायन के कारण एक नई कस्बाई जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण 10– 20 साल पहले तक पहाड़ का उत्पादक श्रम अब अनुत्पादक श्रम पर निर्भर समाज में बदल रहा है।
13. राज्य निर्माण के 22 वर्ष बाद भी हम अधिकांश गांवों तक स्थानीय स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, आसान संचार सार्वजनिक यातायात, स्थाई व टिकाऊ रोजगार, साफ व पर्याप्त पेयजल एवं सिंचाई सुविधाएं स्थापित नहीं कर पाए हैं।
14. हिमालय की भौगोलिक एवं भूगर्भीय संरचना के अनुरूप विकास का मॉडल नहीं बन पाए।
15. विशाल मझोले बांध व सुरंग आधारित जल विद्युत परियोजनाएं बनने का क्रम लगातार जारी है उससे होने वाला पर्यावरणीय तथा सामाजिक विनाश जारी है। टिहरी बांध से विस्थापित गांव आज तक उचित विस्थापन का संघर्ष कर रहे हैं।
16. जंगली जानवर व निराश्रित पालतू पशु प्रदेश निवासियों के जीवन व खेती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, लोगों का जीवन व खेती जानवरों के हमले का शिकार होते जा रही है।
17. जंगलों की आग, गिरता जलस्तर, सूखते जल स्रोत, घटती जैव विविधता, असमय बारिश या सुखा जनजीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है।
18. कोविड-19 के बाद घर वापसी कर चुके नौजवानों या मानव श्रम के सामने रोजगार का संकट बना हुआ है, तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा।
19. शिक्षा खासकर सरकारी शिक्षा के अवसर बड़े हैं बालिका शिक्षा के स्तर में आशातीत सुधार हुआ है। बेहतर होते सरकारी विद्यालयों में रचनात्मक अध्यापकों की बहुत सारी कहानियां और उदाहरण हमको देखने सुनने को मिले।
20. महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है महिलाओं के समूह, सहकारी समूह और संगठन आर्थिक उत्पादन के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रही हैं।
21. स्वतंत्र व अध्ययनशील युवाओं के समूह अपने आस-पास में बदलाव के प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक शोध व हस्तक्षेप की पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन यह अधिकांश प्रयोग शहरों के आस-पास केंद्रित हैं।
22. पहाड़ जो सदियों से सहभागिता व सामूहिकता के मूल्यों से एक दूसरे की सहायता तथा मिलकर अपने बंदोबस्त करते थे अब सरकार पर निर्भर या अनुदान पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिन सार्वजनिक सुविधाओं को हमारे पुरखों ने अपने कौशल, सामूहिक श्रम, नेतृत्व से खड़ा किया अब उनकी देखभाल या पुनर्निर्माण के लिए सरकारी योजनाओं की ओर देख रहे हैं। स्वावलंबी समाज धीरे-धीरे याचक समाज में तब्दील हो रहा है।
23. अनेक स्थानों पर लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों, पंचायती वनों, पानी, नदियों, धराटों की देखभाल करते दिखे।

हमारा समाज जिसका इतिहास व लोक गाथाएं अपने रचनात्मक निर्माण, शांति पूर्ण प्रतिरोध व सामूहिक संघर्षों व जनपक्षीय आवाजों से भरा है जहां विगत 100 वर्षों में जनपक्षीय नेतृत्व व कार्यकर्ताओं की समृद्ध परंपरा रही है वहां अब सामूहिक जनपक्षीय पहले खामोश होने लगी हैं। हम निर्माता या नेतृत्व करता समाज से श्रोता समाज में बदल रहे हैं गलत नीतियों, गलत सूचनाओं, भ्रामक प्रचार के प्रति हमारा रवैया पहले से ज्यादा उदासीन दिखता है।

सद्भावना यात्रा के दौरान हम अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम का लगभग शत-प्रतिशत पालन कर पाये उन समस्त स्थानों पर जा पाये जहां जाने का निर्णय किया था। हमने कोशिश की इस यात्रा के दौरान हम अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं और शिक्षाओं के स्थान पर समाज में प्रचलित अवधारणाओं तथा मान्यताओं को समझ पाए। समाज के सही और गलत को तय करने के विवेक के पास पहुंचे, एक तटस्थ अध्ययन करता के रूप में इस यात्रा को कर पाए। अपने उन तमाम जननायकों के कार्यक्षेत्र व लोग शिक्षण के क्षेत्र में जा पाए जहां उनके काम और विचार के बीज मौजूद हैं।

हमें हमारा समाज तमाम सामाजिक सवालों तथा समस्याओं के बावजूद नए व पुराने ज्ञान व परंपरा के बीच समन्वय बनाता दिखा, चर्चा में भागीदारी करता दिखा, कई चीजों को लेकर आशंकित तो भविष्य को लेकर आशान्वित दिखा, हमारी महान लोकतांत्रिक परंपराओं, भाईचारा, आपसी प्रेम, सामाजिक शांति, व सद्भाव के स्वरो के साथ सहमति जताता दिखा, मुख्य रूप से -

1. सामाजिक सद्भाव के लिए संवाद व सहकार
2. आर्थिक सद्भाव के लिए संवाद व सहकार
3. पर्यावरणीय सद्भाव के लिए संवाद व सहकार

अतः उपरोक्त के लिए व्यापक अवसर व संभावनाएं यात्रा दल को दिखाई देती हैं।



1.5 २१ जून २०२२ – मसीही ध्यान केन्द्र (राजपुर) देहरादून

आज की बैठक का आयोजन सद्भावना के काम को भविष्य में जारी रखने के लिए योजना बनाने हेतु किया गया है। 20 जून 2022 को प्रेस क्लब देहरादून में आयोजित बैठक में सभी प्रतिभागियों ने यह महसूस किया कि भविष्य में सामाजिक व पर्यावरणीय सद्भावना के लिए लगातार संवाद जारी रहना चाहिए।

मसीही ध्यान केंद्र में आयोजित बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन शाह तथा सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष इस्लाम भाई ने संयुक्त रूप से की। सभा का संचालन भुवन पाठक ने किया।

सभा संचालक ने सभा से अनुरोध किया वृ उपस्थित साथी जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हैं, आज केवल भविष्य के कार्यक्रमों का सुझाव देंगे ताकि कोई ठोस योजना बनाई जा सके। यदि उनके कोई सुझाव व प्रस्ताव हों या किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति हो तो उसे भी सदन के सम्मुख रखा जा सकता है।

- कमला पंत ने इस पूरी प्रक्रिया को चौपाल या खुले मंच के रूप में जारी रखने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि सभी कार्यक्रमों की स्वायत्तता बनी रहे इसके लिए सामूहिक तौर पर सद्भावना संवाद चलाये रखना होगा।
- बीजू नेगी ने कहा कि सोशल मीडिया पर घृणा के खिलाफ एक समूह का गठन किया जाए तथा –'हमारे पुरखे' कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर पर भी सद्भावना कार्यक्रमों पर जोर दिया जाए।
- चेतना आन्दोलन के साथी शंकर गोपाल ने वर्किंग ग्रुप बनाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- अजय जोशी ने वैचारिक मिलन, निरंतर संवाद व यात्राओं के आयोजन को महत्वपूर्ण बताया।
- देवेन्द्र बहुगुणा जी ने स्वतंत्र व पूर्णकालिक कार्यकर्ता निर्माण तथा लगातार कोई कार्यक्रम जो बिना लागत व तामझाम के किये जा सकते हों, जैसे स्वधर्म प्रार्थनाय को नियमित करने व करवाने पर बल दिया।
- अर्चना बहुगुणा ने स्थानीय स्तर पर युवा शिविर तथा सद्भावना यात्राएँ आयोजित करने पर बल दिया तथा कहा कि रुद्रप्रयाग में सद्भावना यात्रा तथा सद्भावना शिविर की जिम्मेदारी हम लेते हैं।
- मनीष रावत ने बताया कि नए लोगों की पहचान कर उनको संवाद में कैसे शामिल करें। मनीष रावत ने सद्भावना संवाद को ग्राम स्तर पर ले जाने हेतु वहाँ कार्यरत सामाजिक ईकाइयों जैसे महिला मंगलदल, युवा मंगलदल व ग्राम समितियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा।
- प्रभात ध्यानी ने यात्राओं की जरूरत पर बल देते हुए बताया कि सांप्रदायिक तनाव पर हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। सद्भावना को बढ़ाने के लिए निजी स्तर पर सद्भावना खेलों का आयोजन किया जाए तथा इन आयोजनों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाए।
- डा वसुधा पंत ने कहा कि आगामी वर्षा काल में पूरे प्रदेश में सद्भावना वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाना चाहिए।
- चन्द्रा पंत ने कहा कि युवाओं के साथ युवा शिविर तथा जनगीत आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- रुपेश कुमार ने कहा कि सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाना अति आवश्यक है। किसी भी महत्वपूर्ण घटना पर फेक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाना भी अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है।

- प्रेम बहुखण्डी ने युवाओं के साथ संवाद बनाने के लिए सोशल मीडिया को टूल के रूप में इस्तेमाल करने व उनकी भागीदारी बढ़ाने के बारे में योजना बनानी होगी।
- राजीव गांधी फाउंडेशन के श्री विजय महाजन ने कहा कि सद्भावना संवाद से आगे बढ़कर समाधान तक जाना चाहिए। संवाद के नए माध्यम सोशल मीडिया पर फोकस करना चाहिए। युवाओं को आकर्षित करने वाली विधाओं के बारे में सोचना तथा असहमतियों को सुनना भी चाहिए।

अपने अध्यक्षीय भाषण से पहले राजीव लोचन शाह ने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिये एक संचालन समिति तथा कार्य समिति तय करने का प्रस्ताव सदन में रखा। इस प्रस्ताव के उत्तर में आम सहमति से तय किया गया कि 21 जून 2022 को उपस्थित सभी लोग तथा पूर्व में तय सद्भावना यात्रा समिति के लोग “उत्तराखण्ड सद्भावना संयोजन समिति” के सदस्य होंगे। तथा एक नौ लोगों की कार्यसमिति जो कि सद्भावना कार्यक्रमों का संचालन तथा निगरानी करेगी। तय की गई जिसमें निम्न नाम है :

- 1) सर्व श्री अजय सल्ट – सल्ट जिला अल्मोड़ा; 9411751625
- 2) डा वसुधा पंत – अल्मोड़ा; 9456722422
- 3) गोपाल भाई – बेरीनाग (पिथौरागढ़); 8923523957
- 4) शंकर गौपाल – देहरादून; 8923523959
- 5) अर्चना बहुगुणा – रुद्रप्रयाग; 9690413541
- 6) प्रेम बहुखण्डी – देहरादून; 9810881284
- 7) विनोद बढोनी – घनसाली, टिहरी; 9411734310
- 8) सुरेन्द्र थापा – सहसपुर, देहरादून; 8077882019
- 9) भुवन पाठक – गरुड़, बागेश्वर; 9456813288

यह समिति आगामी एक वर्ष तक उत्तराखण्ड में सद्भावना संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों तथा अभियानों के लिये जिम्मेदार होगी। इसके पश्चात् राजीव लोचन शाह जी ने सभा में वर्ष के लिये कार्यक्रमों मसोदा पेश किया।

1) सद्भावना समितियों का गठन दृ यात्रा के दौरान संपर्क में आये साथियों तथा आयोजन से जुड़े साथियों के साथ जिला स्तर, विकास खंड स्तर व नगर तथा ग्राम स्तर पर सद्भावना समितियों के गठन किया जायेगा।

2) सद्भावना सम्मेलन – आगामी वर्ष भर में प्रदेश में चार सद्भावना सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे। इनका समय व स्थान कार्य समिति की बैठक में तय किया जायेगा।

3) सद्भावना यात्राएँ दृ स्थानीय स्तर पर तीन सद्भावना यात्राओं का आयोजन किया जायेगा

- 1- तराई विकास नगर से बनबसा की यात्रा
- 2- जनपद रुद्रप्रयाग व चमोली की यात्रा
- 3- चंपावत जनपद की यात्रा

4) इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर अन्य प्रयासों तथा सद्भावना कार्यक्रमों के साथ सहभागिता।

इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा सभी साथियों ने इस पर सहमति भी व्यक्त की। तत्पश्चात् सभा अध्यक्ष श्री राजीव लोचन शाह तथा इस्लाम हुसैन जी ने कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की।

सर्वोदय जगत 1-15 जुलाई 22

हल्द्वानी से देहरादून तक; सफल रही राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा

उत्तराखण्ड का जनमानस अपने परम्परागत सद्भाव और भाईचारे की मिसाल खुद है। उत्तराखण्ड में सम्पन्न हुई 40 दिन की राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा में यह तथ्य बार बार देखने को मिला। सभी शांति चाहते हैं और अहिंसा पर टिके रहना उनका स्वभाविक गुण है। यह यात्रा सद्भावना के प्रसार के अपने उद्देश्य में सफल रही।

8 मई को उत्तराखण्ड में हल्द्वानी से आरंभ होकर सद्भावना यात्रा का 20 जून को देहरादून में समापन हुआ। इस यात्रा का मार्ग इस प्रकार निर्धारित किया गया कि उत्तराखण्ड के सभी जिलों और अंचलों में सद्भावना का संदेश पहुंचाया जा सके। यात्रा के दौरान पूरे समय सांस्कृतिक जुलूस निकाले गए, जिनका जबरदस्त प्रभाव स्थानीय जनता पर देखा गया। इस दौरान कुल 80 पड़ावों पर गोष्ठियां और नुक्कड़ सभाएं करते हुए यात्रा देहरादून पहुंची।

इस यात्रा ने जिस तरह राज्य के छोटे-छोटे कस्बों, गांवों, अंचलों, कस्बों, चोटियों और घाटियों को करीब 4500 किमी चल कर नापा है, वह यात्रा की सघनता को समझने के लिए काफ़ी है। इस बीच यात्रा का करीब 10 हजार लोगों से सम्पर्क हुआ, जिसमें करीब 800 लोग ऐसे थे, जिन्होंने यात्रा के दौरान कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय सहयोग किया।

यात्रा के दौरान उत्तराखण्ड के जिन जननायकों का जिक्र बार बार आया, उनमें वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली का नाम प्रमुख है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली ने जिस तरह पेशावर के किस्साखानी बाजार में निहत्थे आंदोलनकारी पठानों पर गोली चलाने से इंकार किया था, वह सचचाई और साहस की अद्भुत मिसाल है।

उत्तराखण्ड का भूगोल, जलवायु और सांस्कृतिक विविधता हमें एकता का संदेश देती है। उत्तराखण्ड में करीब डेढ़ दर्जन भाषा और बोली बोलने वाले हैं, जो आपसी सद्भाव से रहते हैं। यात्रा में सामाजिक, जातिगत और धार्मिक मुद्दों पर जन सामान्य से बातचीत करके वर्तमान परिस्थितियों में समन्वय और सद्भाव बढ़ाने पर बल दिया गया।

यात्रा में अस्मादित मजदूरों व महिलाओं की स्थिति, किशोर-किशोरियों व युवाओं के मुद्दे, निराश्रित महिला पुरुषों के अलावा सड़कों और जंगलों में घूमते हुए निराश्रित पशुओं की दुर्गति पर भी चिंता व्यक्त की गयी। पलायन से खाली होते गांवों, प्राकृतिक संसाधनों और पशुधन की हिराजत जैसे मुद्दों और मौजूदा हालात पर भी विचार विमर्श हुआ।

जलवायु परिवर्तन के कारण प्रदेश में कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बंजर होते खेतों और बागीचों की जमीनों पर बनने वाले रिजोर्ट और बड़े बड़े निर्माणों से स्थानीय संरचना पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की अपनी चिन्ताओं को लोगों ने यात्रीदल के साथ साझा किया। बागवानी, कृषि उत्पादन, फलो-

त्पादन, दुग्ध उत्पादन और स्वरोजगार के अच्छे प्रयोगों और अनुभवों को भी साझा किया गया।

यात्रा के दौरान सबसे प्रभावकारी नुक्कड़ सभाएं रहीं, जिनमें यात्रीदल ने विभिन्न विषयों पर आमजन से सम्भाषण किया। गोपाल भाई के जन गीतों से आरंभ होने वाली नुक्कड़ सभाओं में भुवन भट्ट, इस्लाम हुसैन और साहब सिंह सजवाण ने अपनी बात रखी, राज्य के आंदोलनकारी व जुझारू नेता पीसी तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि सद्भावना के माहौल में ही राज्य का विकास हो सकता है। उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों के लिए श्रद्धा का केन्द्र रहे गैरहैन में राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा का स्वागत करते हुए जुझारू नेता कामरेड इंद्रेश मैखुरी ने सभी विभाजनकारी और साम्प्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करने का आह्वान किया।

पंचश्री बसंती बहन ने अपने हर सम्बोधन में जल, जंगल, जमीन की लूट और नशे के बढ़ते प्रचलन को देश और प्रदेश के लिए पातक बताया और इसे रोकने की अपील की। कोसी नदी घाटी में किए गए उनके कार्यों व अनुभवों को सुना और सराहा गया। स्कूलों में छात्र छात्राओं को इस बात से ख़ास खुशी हुई कि उनके बीच पंचश्री से सम्मानित बसंती बहन पहुंची हैं।

प्लास्टिक कचरे के खतरे पर भी चर्चा हुई, लोगों का कहना था कि कचरे के कारण पहाड़ के सौंदर्य और पर्यावरण पर संकट आ गया है, सरकार के पास इस समस्या को दूर करने के लिए न दृष्टि है और न ही इच्छा है। यात्रा के अन्तिम पड़ाव देहरादून के पास यात्री दल खाराखेत पहुंचा, जहां की खारी नदी में स्थानीय सत्याग्रहियों ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। यात्री दल ने वहां दांडी मार्च के सत्याग्रहियों को याद किया।

इस यात्रा में जो लोग सम्मिलित रहे, उनमें उत्तराखण्ड सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष इस्लाम हुसैन, यात्रा संयोजक भुवन पाठक, चिपको आंदोलनकारी साहब सिंह सजवाण, पंचश्री बसंती बहन, उत्तराखण्ड आंदोलनकारी पीसी तिवारी, सामाजिक मुद्दों पर मुखर व आंदोलनकारी प्रभाव ध्यानी, सर्वोदय मण्डल से रीता इस्लाम, सुरेन्द्र बरोलिया, नरेंद्र कुमार, राजीव गांधी फाउंडेशन से विजय महाजन, परमानंद भट्ट, हिदायत आजमी, जीत सिंह, लक्ष्मी, प्रयाग भट्ट, रजनीश और रेवा अरुण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

सर्वोदय जगत डेस्क



2 Governance and Development - Bihar – An overview of the environmental, socio-economic and fiscal situation

Vijay Mahajan and Dr Rakesh Ranjan

A presentation titled Bihar – Dasha aur Disha was made by an RGICS Team at Bihar Vimarsh, Muzaffarpur, 21 May 22. Its first half- Dasha – or status report is presented below. The second half – on Disha – direction for progress is also available to interested readers upon request. Both part of the presentation are available in Hindi as well.

2.1 Environmental Conditions of Bihar

2.1.1 Jal - Water – floods

- Bihar is India's most flood-prone state, with 76% population in the North Bihar living under the recurring threat of flood devastation. Bihar makes up 16.5% of India's flood affected area and 22.1% of India's flood affected population.
- About 73.1 % of Bihar's geographical area, i.e. 68,800 square kilometres out of 94,160 square kilometres, is flood affected. Sixteen per cent of the land mass of north Bihar is subject to permanent water logging.
- Floods are an annual phenomenon in North Bihar, due to five major rivers during monsoon – Mahananda, Koshi, Bagmati, Burhi Gandak and Gandak – which originate in Nepal. Some south Bihar districts are vulnerable to floods from Son, Punpun and Phalgu.
- In 2021, over 83.62 lakh people across 16 districts, 130 blocks and 1,333 panchayats were affected as per the Disaster Management Department.
- As per Government records, since 1979, over 9500 people died in floods. In 2021, flood-related deaths were 27. The highest 11 casualties were in Darbhanga district, followed by 6 in Muzaffarpur, 4 in West Champaran and 2 each in Saran, Siwan and Khagaria.

2.1.2 Jal - Water – Drought

- At the same time, there is water scarcity, even in the flood affected districts.
- The groundwater level has fallen in eight of Bihar's 38 districts compared to 2020, as per a recent survey by the state's Public Health Engineering Department (PHED).
- Eleven districts of the Bihar have been put in the 'water-stressed' category. Districts like Muzaffarpur, Darbhanga and Gaya are already facing water shortage with pumps, wells and ponds drying, according to media reports.

- Arwal, Banka, Kaimur, Bhagalpur, Samastipur, Bhojpur, Buxar and Patna are also staring at water crisis, which is imminent when groundwater dips below 25 feet.
- The survey categorised the panchayats into five groups according to the extent of depletion. The report termed 498 panchayats as 'sensitive'.

2.1.3 Jangal - Forests

- Before the abolition of Zamindari, Bihar had a system of “private forests” and to ensure that these were not cut down, the Bihar Private Forest Act, 1947 was promulgated before the abolition of Zamindari. However, it had little effect. There was over 20,000 km² of private forests in undivided Bihar before 1947.
- Today, Bihar has a notified forest area of 7306 km², which is 7.76% of its land area, with only Kaimur and West Champaran having nearly 1000 sq km each, (Source: Forest Survey of India 2019).
- Bihar has 12 wildlife sanctuaries/national parks, the three biggest being Kaimur, Valmiki in West Champaran and Bhimbandh in Munger district.
- Only 121 of 8022 Individual Forest Rights claims received had been settled till Dec 2021, vs. 19.75 lakh out of 41.27 lakh claims All India as per MOTA website.

2.1.4 Jameen – Land and Soil

- Bihar has about 8.63% of the total population in the country while the share in total land area of India is only 2.86% or 9360 km² of which 5353 km² or 57% is net sown area (agri).
- Wasteland covers 6.90 % (6,501 km²) of the state with dominance of waterlogged areas in North Bihar (25.28 %) and scrubland (26.61 %) in South Bihar.
- With proper treatment, this wasteland has the possibility of generating livelihoods for 5 lakh landless families and another 5 lakh fisherfolk in waterlogged areas.

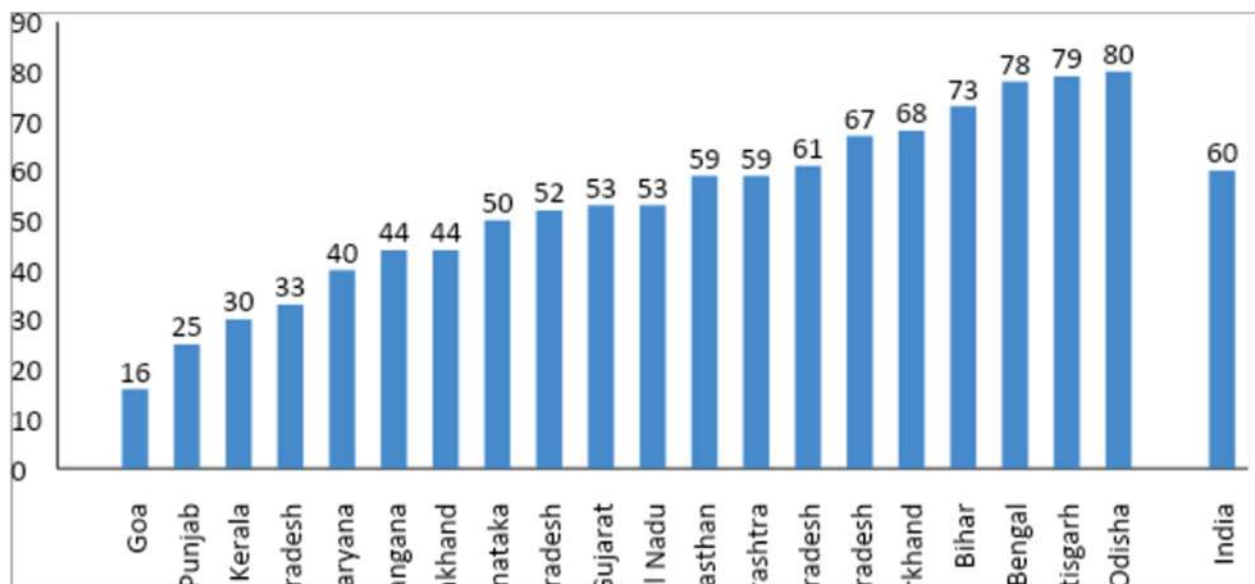
Wasteland categories	North Bihar (area in km ²)	% of total wasteland	South Bihar (area in km ²)	% of total wasteland
Gullied/ravinous land			91.59	1.41
Land with dense scrub	842.44	12.96	192.07	2.95
Land with open scrub	708.73	10.90	1,701.37	26.16
Waterlogged-permanent	779.22	11.98	28.90	0.44
Waterlogged-seasonal	845.36	13.00	54.97	0.84
Land affected by salinity/alkalinity	10.12	00.15		
Scrub forest	52.32	00.80	957.70	14.73
Agricultural land inside notified forest land	4.05	00.06	22.48	0.34
Degraded pastures/grazing land	7.82	00.12	1.80	0.03
Degraded land under plantation crops	8.25	00.13	3.29	00.05
Sands-riverine	49.77	00.76	11.79	0.18
Mining wasteland	0.22	00.003		
Industrial wasteland			0.90	0.01
Barren rocky area			115.25	1.77

2.2 Social conditions of Bihar

2.2.1 Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Vulnerable Rural Households (2011)

State	SC%	ST%	Total population of SC, ST in 2011
All India	18	11	17.98 crore
Bihar	17	2	1.78 crore
UP	24	1	2.60 crore
Kerala	10	2	0.63 crore

In Bihar **73% of the rural households or 1.3 crore households** were identified as vulnerable as per the Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011, as compared to UP 67%, Kerala 30% and All India 60%. This was despite less than national average of Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST). After the split of Jharkhand, there is very little scheduled tribe population in Bihar.



Within Bihar, there is greater degree of vulnerability in North Bihar, where most districts (except Gopalganj, Chhapra and Siwan) have uniformly higher deprivation percentage. This is also reflected in higher percentage of landless casual labourers and lower educational attainment.

District Name	%Deprived HH	Housing	SC/ST HH	Education	Landless Casual
All India	49	13	22	24	30
BIHAR	61	20	16	34	47
Katihar	73	20	13	50	59
Darbhanga	73	39	15	45	57
Khagaria	73	35	13	43	61
Kishanganj	71	11	10	47	58
Begusarai	71	34	13	36	59
Purnia	70	18	15	47	53
Saharsa	70	32	17	43	54
Araria	69	22	13	43	52
Sheohar	68	19	14	46	53
Sitamarhi	68	24	11	45	51
Munger	68	23	15	32	60
Madhepura	67	27	16	47	44
Samastipur	67	33	18	36	50
Vaishali	66	29	20	31	56
Supaul	63	18	14	39	46
W. Champaran	61	15	19	36	48
Muzaffarpur	61	20	15	32	46
Bhagalpur	61	22	10	30	51
Banka	61	24	15	33	41
E. Champaran	60	17	11	33	48
Madhubani	59	20	12	33	43
Patna	57	14	16	28	50
Gaya	56	9	31	33	41
Jamui	56	16	19	30	35
Lakhisarai	55	17	14	30	44
Sheikhpura	55	13	20	32	47
Nawada	55	9	25	30	46
Arwal	54	10	19	24	47
Aurangabad	53	9	23	21	46
Nalanda	52	12	17	28	45
Jehanabad	52	11	17	27	45
Bhojpur	51	13	15	20	45
Rohtas	50	13	20	20	43
Saran	47	15	12	24	29
Buxar	44	7	15	15	38
Gopalganj	42	8	13	24	22
Siwan	42	10	13	21	25

2.2.2 Education

One in six children do not enter school. Of the ones who enter school, only one child out of five finishes higher secondary (12th). As can be seen from the table below, while the net enrolment rate in Bihar in the elementary level is only slightly less than the All India average and even the best state, Kerala, the enrolment rate drops at the secondary level to half of Kerala and then to one-fourth of Kerala by the Higher Secondary level.

Net Enrolment Rate by Gender and Level of School Education 2019-20

State	Elementary (I-VIII)			Secondary (IX-X)			Higher Secondary (XI-XII)		
	Girls	Boys	All	Girls	Boys	All	Girls	Boys	All
Kerala	93	93	93	74	74	74	66	59	62
Uttar Pradesh	89	86	87	36	39	37	26	27	26
Bihar	87	83	85	36	34	35	16	16	16
India	91	90	90	50	50	50	33	31	32

Retention Rates across States in India by Level of Education

State	Elementary (I-VIII)			Secondary (IX-X)			Higher Secondary (XI-XII)		
	Girls	Boys	All	Girls	Boys	All	Girls	Boys	All
Kerala	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Uttar Pradesh	61	62	62	61	54	58	45	40	42
Bihar	73	79	76	43	46	45	19	19	19
All India	74	75	75	60	60	60	40	40	40

Dropout rate is higher among north Bihar districts. Dropout rates are higher for SCs as compared to OBC children in both upper primary than secondary levels in the most districts, but both are high.

2.2.3 Higher education in Bihar

In 2020, Bihar had 35 universities and 874 colleges.

There are over 17 lakh students in higher education in Bihar, of which 2.1 lakh are in Universities and the rest in colleges/technical institutes.

Overall enrolment rates are 14.5%, while for SC women it is 8.5%. The state is taking steps for increasing the gross enrolment ratio in higher education to 50% by 2035. Gender parity index was 0.8 overall and only 0.6 for SC girls.

Bihar allocated 19% of its total expenditure to education in 2021-22 vs the average allocation (15.8%) for education by all states.

2.2.4 Health as per NFHS IV and V

Bihar Health Parameters – National Family Health Survey	NFHS-5 2019-20			NFHS-4 2014-15
	Urban	Rural	Total	Total
Access To Electricity	96.2	96.3	96.3	60
Access To Drinking Water	99.5	99.2	99.2	98.4
Access To Sanitation	69.2	45.7	49.4	26.5
Access To Clean Fuel	78.6	30.3	37.8	17.8
Access To Health Insurance	11.6	15.1	14.6	12.3
Neonatal Mortality Rate (NNMR)	29.5	35.2	34.5	36.7
Infant Mortality Rate (IMR)	43.1	47.3	46.8	48.1
Under-Five Mortality Rate (U5MR)	50	57.4	56.4	58.1
Antenatal Care 4 Visits	32.4	24	25.2	14.4
Iron Folic Acid For 180 Days	15.3	8.3	9.3	2.3
Mother And Child Protection (MCP) Card	85	90.2	89.5	79.9
Postnatal Care (2 Days)	62.6	56.5	57.3	42.3
Institutional Births (%)	84.1	75	76.2	63.8

Bihar was ranked 18th out of 19 major states ranked on health status by the NITI Aayog. UP was the last at no 19. Kerala was number 1.

Between 2014-15 and 2019-20, there has been an improvement in most parameters related to child immunization, nutrition and adult nutrition.

The one exception in this regard is anaemia among women of all ages.

The budget allocation for health in Bihar was 6.3% of total expenditure, higher than the average allocation for health by all states (5.5%).

Bihar Health Parameters – National Family Health Survey Child Immunization, Nutrition and Adult Nutrition Status	NFHS-5 2019-20			NFHS-4 2014-15
	Urban	Rural	Total	Total
Children Age 12-23 Months Fully Vaccinated	66.7	71.6	71	61.7
Children Under 5 Years Who Are Stunted	36.8	43.9	42.9	48.3
Children Under 5 Years Who Are Wasted	21.6	23.1	22.9	20.8
Children Under 5 Years Who Are Severely Wasted	7.7	9.0	8.8	7.0
Children Under 5 Years Who Are Underweight	35.8	41.8	41	43.9
Women Body Mass Index (BMI) Below Normal	18.7	26.9	25.6	30.4
Men Body Mass Index (BMI) Below Normal	12.9	23.8	21.5	25.4
Non-Pregnant Women Age 15-49 Years – Anaemic %	66.0	63.1	63.6	60.4
Pregnant Women Age 15-49 Years – Anaemic %	56.1	63.9	63.1	58.3

2.3 Economic conditions of Bihar

2.3.1 GSDP, Per Capita Income & Unemployment

• **Gross State Domestic Product (GSDP):** The growth rate of Bihar's GSDP (at current prices) was 9.8% in 2021-22, higher than the growth rate of India (8.9%). **GSDP for 2021-22 (at current prices) was projected to be Rs 7,57,026 crore.** This is an annual increase of 11% over the GSDP in 2019-20.

• **Per capita income:**

• The per capita income of Bihar in 2019- 20 (at constant prices of 2011-12) was Rs 34,413 or 8.8% higher than the corresponding figure in 2018-19.

• But it was less than a third of the average per capita income of India which was Rs 107,589 in 2019- 20 (at constant prices of 2011-12).

• Within Bihar, the per capita income varied from Rs 112,604 the highest in Patna district to Rs 17,569, the lowest in Sheohar dt. North Bihar districts have lower PCI.

• **Unemployment:** According to the Periodic Labour Force Survey (July 2018-June 2019), the unemployment rate among all age groups in Bihar was 10.2%, significantly higher than that at the all-India level (5.8%).

2.3.2 Output (GSDP) and its growth - Bihar vs Other States

Rs Billion (00 crore) at constant 2011-12 Prices

GSDP in	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
Kerala	3640	3877	4028	4200	4512	4853	5162	5497	5686	5143
Uttar Pradesh	7241	7582	8021	8344	9082	10115	10577	11240	11668	NA
Bihar	2471	2569	2696	2795	2965	3188	3440	3814	4096	4199
All India	87363	92130	98013	105276	113694	123081	131446	140033	145692	135127

Growth rate of GSDP in % pa	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
Kerala	7	4	4	7	8	6	6	3	
U. Pradesh	5	6	4	9	11	5	6	4	
Bihar	4	5	4	6	8	8	11	7	
All India	4.2	5.0	6.1	6.7	6.9	5.6	5.5	3.0	-8.2

2.3.3 Per capita income District-wise for Bihar 2017-18

Districts	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Patna	91407 (1)	90124 (1)	98380 (1)	107349 (1)	112604 (1)
Nalanda	21453 (12)	23135 (9)	24012 (10)	25539 (9)	26200 (9)
Bhojpur	22723 (7)	22355 (13)	24607 (7)	24216 (14)	25683 (13)
Buxar	21648 (10)	22155 (15)	23583 (11)	25168 (10)	25912 (12)
Rohtas	24192 (6)	24838 (7)	25692 (6)	27246 (6)	27804 (6)
Kaimur	20358 (20)	20813 (18)	20468 (19)	21641 (24)	22464 (22)
Gaya	22076 (8)	24321 (8)	24485 (9)	26897 (7)	27695 (7)
Jehanabad	21551 (11)	22710 (11)	22975 (12)	24471 (13)	25219 (14)
Arwal	16023 (36)	17751 (33)	17556 (34)	20034 (31)	20550 (30)
Nawada	15955 (37)	17079 (35)	17137 (36)	18711 (34)	19329 (35)
Aurangabad	21946 (9)	23064 (10)	24605 (8)	26500 (8)	26795 (8)
Saran	18806 (26)	18478 (29)	18505 (29)	20851 (25)	20921 (27)
Siwan	18992 (25)	20053 (21)	20322 (20)	21791 (21)	22638 (19)
Gopalganj	21154 (14)	18790 (26)	19057 (28)	20291 (29)	21094 (26)
W. Champaran	21235 (13)	22515 (12)	22649 (14)	23638 (16)	24223 (16)
E. Champaran	16530 (35)	18326 (31)	18104 (31)	20493 (28)	20421 (31)
Muzaffarpur	25282 (5)	26177 (5)	26559 (5)	28844 (5)	29375 (5)
Sitamarhi	17195 (31)	17505 (34)	18184 (30)	19856 (32)	20078 (32)
Sheohar	15609 (38)	15842 (38)	15691 (38)	17209 (38)	17569 (38)
Vaishali	21129 (16)	21732 (16)	22462 (15)	24945 (12)	26067 (11)
Darbhanga	20679 (18)	22281 (14)	22940 (13)	24133 (15)	26170 (10)
Madhubani	17229 (30)	18506 (28)	17973 (32)	18061 (37)	20020 (33)
Samastipur	19098 (24)	19586 (23)	20310 (21)	21705 (23)	23981 (17)
Begusarai	39914 (2)	35235 (2)	46068 (2)	44857 (2)	45540 (2)
Munger	30603 (3)	32194 (3)	33563 (3)	35979 (3)	37385 (3)
Sheikhpura	16645 (34)	19253 (24)	19383 (27)	20280 (30)	21122 (25)
Lakhisarai	20603 (19)	20728 (19)	21581 (17)	25162 (11)	24297 (15)
Jamui	21140 (15)	25935 (6)	22259 (16)	22909 (17)	22479 (21)
Khagaria	18056 (28)	18817 (25)	19754 (24)	22137 (19)	22132 (23)
Bhagalpur	30581 (4)	30993 (4)	32450 (4)	33992 (4)	34980 (4)
Banka	19372 (22)	18406 (30)	19682 (25)	20722 (27)	20920 (29)
Saharsa	20771 (17)	20371 (20)	20788 (18)	22476 (18)	23416 (18)
Supaul	17019 (32)	16865 (36)	17770 (33)	18342 (36)	19743 (34)
Madhepura	19493 (21)	19738 (22)	19833 (22)	20784 (26)	22633 (20)
Purnea	18583 (27)	18570 (27)	19678 (26)	21746 (22)	21813 (24)
Kishanganj	17412 (29)	17875 (32)	17542 (35)	19210 (33)	19313 (36)
Araria	16835 (33)	16759 (37)	17118 (37)	18665 (35)	18981 (37)
Katihar	19350 (23)	20841 (17)	19823 (23)	21869 (20)	20921 (28)
Bihar	24874	25379	26504	28419	29385

Patna, the most urbanised district, with a high share of non-farm sector services, construction and manufacturing, has the highest per capita income. This is followed by Begusarai, Munger and Bhagalpur, all more with more non-farm sector. The lowest are districts like Sheohar, Araria, Kishanganj, Sitamarhi and Madhubani – with flood affected agricultural livelihoods.

2.3.4 Agriculture

- Farm holdings are small and scattered. There are about 1.61 crore farm holdings of which 91 percent is marginal, with average holding size of 0.33 ha or 0.75 acres.
- Agriculture and allied sector contributes 18.9 percent of the GSDP. The rate of growth of agriculture and allied sector has been 5.4 percent during 2005-10 and 3.7 percent during 2010-14.
- The recurrent floods in N Bihar and droughts in S Bihar are major obstacles.
- In terms of yield, Bihar's average is slightly above all India in wheat and paddy, and double of all India in Maize and pulses. Sugarcane is near average yield but lower in sugar content. Jute is grown in Seemanchal districts.
- Bihar is a major fruit and vegetable growing state. Total vegetable production in Bihar is about 157 lakh tonnes. Potato, Onion, Tomato, Brinjal, Okra and Cauliflower are the major vegetable crops.
- The four most important fruit crops in Bihar are mango, guava, litchi and banana.
- Processing of cereals, fruits, vegetables is minimal. Only sugarcane and milk are processed due to perishability.

2.3.5 Livestock

- **Overall:** Of the 36.5 million livestock in Bihar, 15.3 million are milch cattle, 7.7 million are buffaloes, and 12.6 million are goats. Bihar is not among the top 10 states in poultry.
- **Dairy:** Out of total 198 million tons of milk production in 2019-20 in India, Bihar accounted for a mere 10.8 million tons or about 5.5% as against about 7.7% of the cattle and buffalo population of India. The daily milk production of crossbred cattle is 6, 7, and 5.5 litres/day in the Northern, Central and Southern zones, respectively.
- **Milk Processing:** Currently, there is a capacity to process 13% of the total milk produced into various milk products (pasteurized milk, UHT, powdered milk, ice cream, butter, ghee etc.). The govt has targeted that 32% of the milk will be processed by 2032–33.
- **Fishery:** The water area of Bihar constitutes about 3.9 percent of the total geographical area. In 2004-05, the production of fish in Bihar was 2.67 lakh tonnes. The production grew continuously thereafter and reached the peak level of 4.32 lakh tonnes in 2013-14.

2.3.6 Infrastructure, Industry & Services

- **Infrastructure:** Rail and highway network is adequate but mainly a “pass through” rather than used for local growth purposes. The construction of the Patna-Kolkata Expressway, covering about 450 kilometres is expected to cost Rs 18,000 crore has been announced. It will pass through five districts of Bihar.
- **Power:** Installed power generation capacity in Bihar was 6385 MW as of April 2020. New projects under construction which will take generation capacity to more than 12000 MW.
- **Industrial sector** is hampered by lack of infrastructure – power, district and city roads, industrial sheds, as well as inadequate credit from banks. Bihar has 68 industrial areas and mega industrial parks. Most are moribund.
- **Service sector** in Bihar is largely informal, covering retail trade, transport, storage, hotels and restaurants, and education, health and public services.
- **Tourism:** Foreign tourist arrival in Bihar was 10.9 lakh in 2019, about 10% of India. The main attraction is the sites related to Mahatma Buddha. Domestic tourism is largely religious and historical.

2.4 Financial situation of Bihar - State finances

2.4.1 Budget Highlights¹

- **Total expenditure** for 2021-22 was estimated to be Rs 2,18,303 crore, an annual increase of 23% over the actual expenditure in 2021-21.
- **Total receipts (excluding borrowings)** for 2021-22 are estimated to be Rs 1,86,697 crore, an annual increase of 23% over the actual receipts in 2019-20. In 2020-21, total receipts (excluding borrowings) are estimated to fall short of the budget estimate by Rs 9,684 crore (a decrease of 5%).
- **Revenue deficit** in 2021-22 the state has estimated a revenue deficit of Rs 5,187 crore (0.8% of GSDP).
- **Fiscal deficit** in 2021-22 is estimated to be Rs 22,511 crore (2.97% of GSDP). As per revised estimates, in 2020-21, fiscal deficit is estimated to be 6.77% of GSDP, which is significantly higher than the budget estimate of 2.97% of GSDP.

¹ Source: psindia.org, State Budget

2.4.2 State budget expenditure pattern

The figures below compare Bihar's expenditure on six key sectors as a proportion of its total expenditure on all sectors.

- **Education:** Bihar has allocated 19% of its total expenditure for education in 2021-22. This is higher than the average allocation (15.8%) for education by all states.
- **Health:** Bihar at 6.3% has a higher than average allocation for health by states (5.5%).
- **Agriculture and allied:** Bihar 3.7%, much lower than the average allocation for agriculture by states (6.3%).
- **Rural development:** Bihar 11.6%, almost double average for rural development by states (6.1%).
- **Police:** Bihar 5.6%, higher than the average expenditure on police by states (4.3%).
- **Roads and bridges:** Bihar 3.8%, lower than the average allocation by states (4.3%).
- **Committed expenditure (salaries, pensions, interest on borrowings)** was 33.1%.

2.4.3 Banking, Savings, Credit and Investment

- **Branch Network:** There were 6900 bank branches in Bihar in 2019, 5.7% of 145,000 all India. Population per branch was 16,000 vs 11,000 all India.
- **Bank Deposits** of Bihar in 2019 were Rs 3.5 lakh crore, or 2.6% of 136 lakh crore all India. Per capita savings was only about Rs 29,000 in Bihar as against about Rs 101,000 for India.
- **Mutual Funds** have become popular means of saving in Bihar. By 2022, the amount invested in MFs was Rs 32,254 crore. (Source: livehindustan.com dated 11 Feb 2022).
- **Bank Credit** in Bihar in 2019 was Rs 1.24 lakh crore, or 1.25% of Rs 98.9 lakh crore all India. Per capita credit was only about Rs 10,000 in Bihar as against about Rs 73,000 for all India. (Source: RBI). Thus for every Rs 100 saved in Bihar, only Rs 35 is coming back as credit.
- **Credit through Self-Help Groups (SHGs)** - As on 31 Mar, 2020, 6.9 lakh SHGs in Bihar were linked with Banks, with credit o/s of Rs 6,966 crore vs Rs 108,075 crore all India for 56.8 lakh SHGs (Source: NABARD SHG Report, 2021).
- **Microfinance** – There were 60 MFIs with 2103 branches, 45.34 lakh borrowers, Rs 9946 cr loans outstanding. Disbursement in 2021 was Rs 8,234 crore, 25% lower than 2020. Despite that Bihar was no 3 state in India in microfinance (Source: Bharat Microfinance Report 2021).
- **Investment** – In 2021, Bihar has received investment proposals worth Rs 39,000 crore. However, of this, Rs 30,382 crore were related to ethanol production alone. Foreign Direct Investment was Rs 1252 cr in 2021. (Source: Udyog Mitra, InvestIndia).

2.4.4 Development programs for the poor – Rations, MGNREGA

- As per the National Food Security Act (NFSA) portal, there were 1.79 crore ration card holders in Bihar and 8.71 crore people are benefiting from rations under the PDS.
- There were 22.9 lakh beneficiaries of the Antyodaya Anna Yojana (AAY) under which poorest households can purchase up to 35 kilograms of rice and wheat at a highly subsidised cost of ₹3 per kilogram of rice and ₹2 per kilogram of wheat. . Recall there were 1.3 crore vulnerable rural households in Bihar.
- There were 1.56 crore Priority Household (PHH) beneficiaries in the state for rural families. PHH cardholders are not in AAY, yet receive 5kg of food grains per person per month at the same price as AAY beneficiaries.
- As per the MNREGA portal, there were 2.41 crore Job Cards issued with 3.29 crore workers. However, only 82.8 lakh job cards and 92.6 lakh workers were actively engaged as on 11th May 2022, which is the peak season. Recall there were 1.3 crore vulnerable rural households in Bihar.
- In the COVID pandemic, MNREGA was used a lot. In FY 2020-21, and 2021-22, 2.28 crore and 1.82 crore person-days were generated, in 21 and 11 lakh works, with average wages of Rs 198 and Rs 194 per day respectively. The total NREGA expenditure was Rs 6425 crore and Rs 6514 crore respectively.

Under the Bihar Rural Livelihoods - Jeevika program, over 10.7 lakh self-help groups (SHGs) of women have been formed and 6.9 lakh SHGs in Bihar were linked with Banks, with credit o/s of Rs 6,966 crore. Total number of poor households covered is over 1.5 crore.

Saat Nishchay-2 Yojana: Rs 4,671 crore has been allocated in 2021-22 for this Yojana:

- i) creating centres of excellence in polytechnics and industrial training institutes,
- ii) establishing mega-skill development centre in each district, and tool rooms in each division,
- iii) providing grants up to Rs 5 lakh and loan up to Rs 5 lakh at a subsidised interest rate to youth and women for setting up new businesses,
- iv) providing cash incentive to female students: Rs 25,000 upon completing senior secondary and Rs 50,000 upon completing graduation,
- v) provision of telemedicine, pathology, and screening for diabetes, blood pressure etc. in primary healthcare centres,
- vi) housing for homeless and landless poor in urban areas, and shelter homes for old age persons in all cities
- vii) Under Digital Bihar Program, all students of Class VI and above will receive computer education and training from 2021-22 onwards.



3 Growth with (out) Employment - Worrying trends from Gujarat (compilation from various sources)

3.1 Gujarat's industrial clout keeps growing

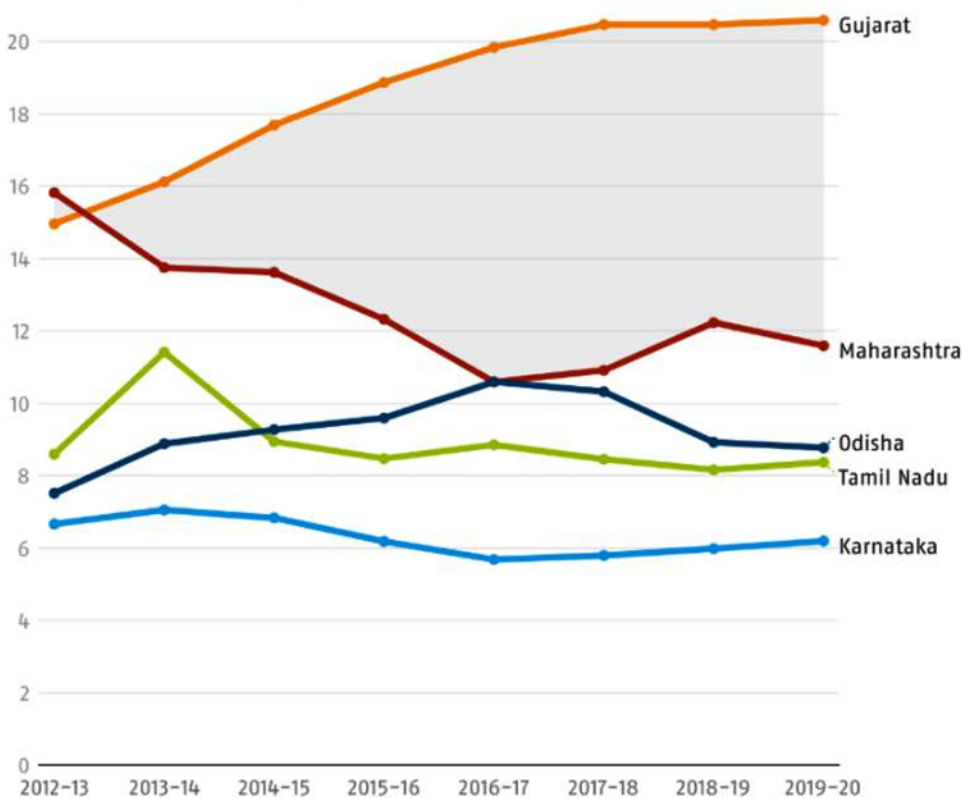
Gujarat has more machinery, equipment, buildings and other factory assets than any other Indian state, and the gap keeps growing as governments compete to get industrial investment.

Gujarat's share in the total value of such assets--called fixed capital--nationwide has increased from 14.96 per cent in 2012-13 to 20.59 per cent in 2019-20, shows data from the Annual Survey of Industries which tracks organised manufacturing across India. The government releases the data with a lag. It put out the provisional data for 2019-20 in May 2022.

The fixed capital share of other top industrial states, like Maharashtra, Tamil Nadu and Karnataka, declined in the same period as seen in chart 1

Gujarat now accounts for over a fifth of India's fixed capital

Shows share of total fixed capital (in %)



Data for top 5 states in terms of fixed capital as of 2019-20

Source: Annual Survey of Industries, Business Standard calculations

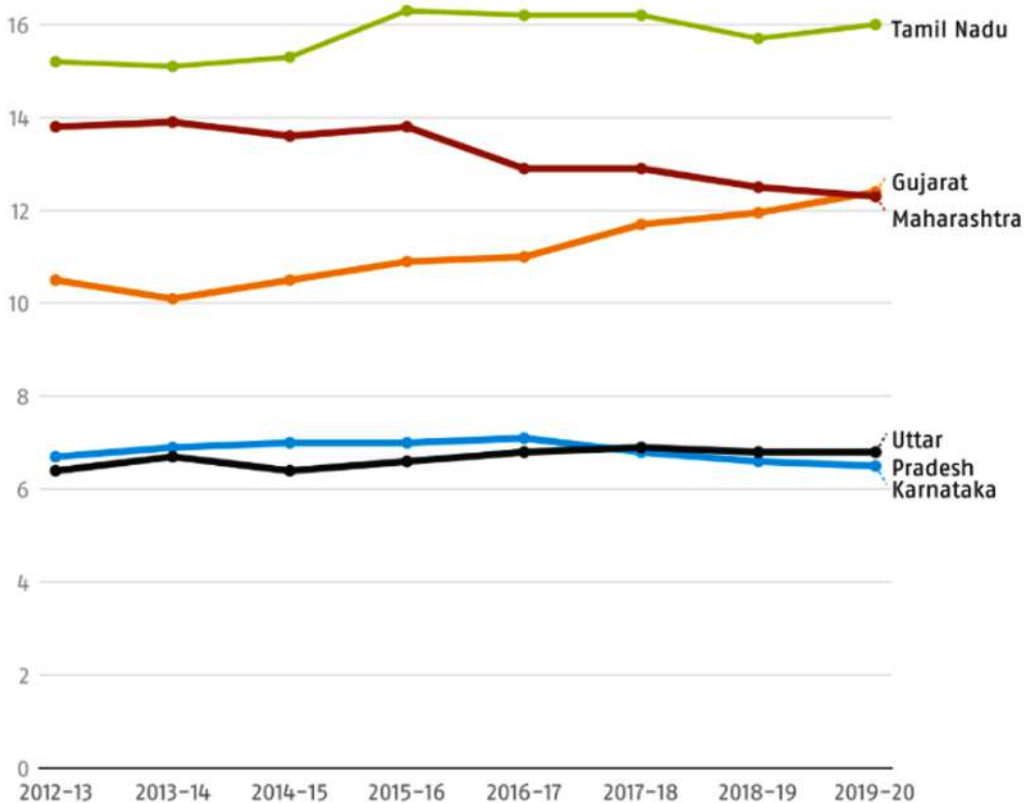
Gujarat takes a dominating share of productive capital as well. Productive capital includes assets like raw materials, semi-finished goods and cash, in addition to fixed assets. Gujarat’s share of productive capital has gone up from 15.1 per cent in 2012-13 to 19 per cent in 2019-20.

Gujarat gets the largest share of capital investment, but Tamil Nadu maintains the record of having the highest number of factories. It accounts for 15.8 per cent of India’s factories by number. Gujarat is second with an 11.6 per cent share, followed by Maharashtra at 10.4 per cent.

There is a similar trend in the share of persons engaged in manufacturing. This includes all workers, working proprietors and family members, as well as unpaid persons engaged in factory work. Tamil Nadu tops in terms of providing the highest number of such factory jobs, taking a 16 per cent share in the national total. Gujarat replaced Maharashtra in the second spot in the latest survey. It had a 12.4 per cent share compared to Maharashtra’s 12.3 per cent for 2019-20 (see chart 2).

Tamil Nadu provides the most factory jobs

Share of total persons engaged (in %)



Data for top 5 states in terms of persons engaged as of 2019-20

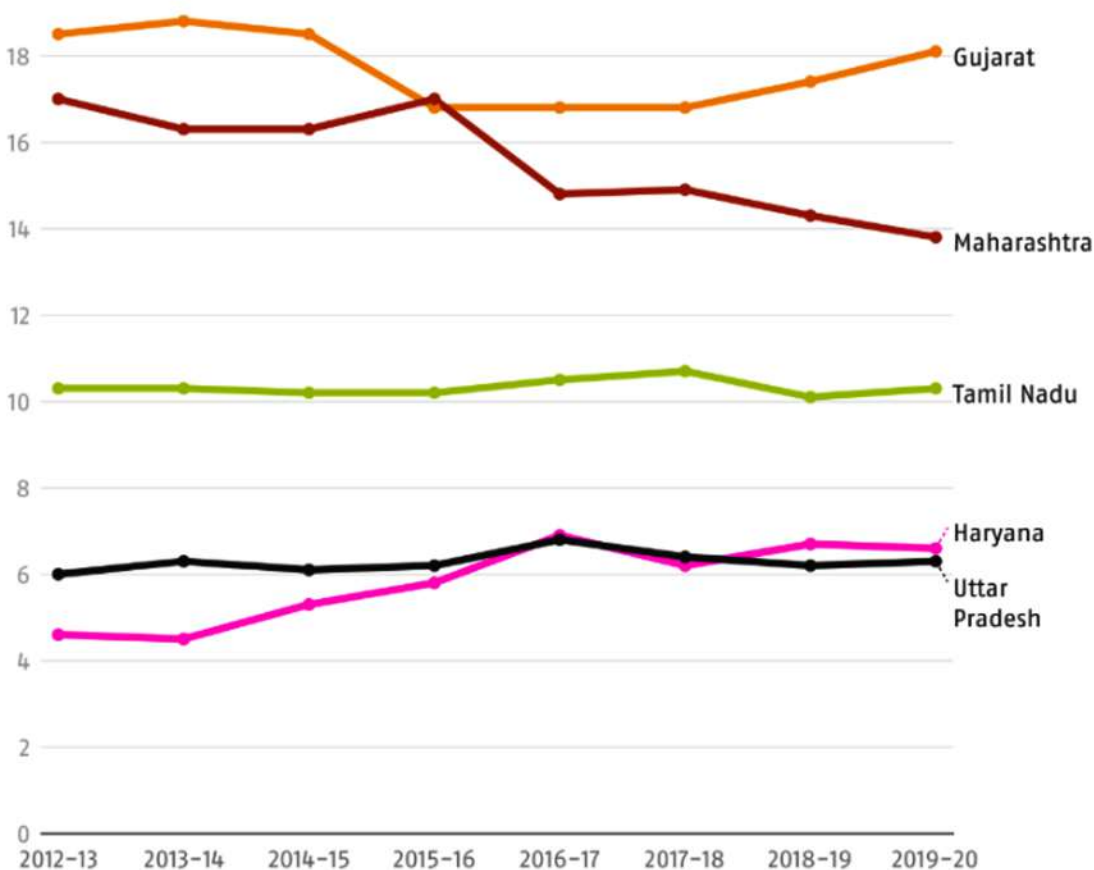
Source: Annual Survey of Industries, Business Standard calculations



The share in the value of output from factories has not changed much for industrialised states. Gujarat maintained the top spot with an 18.1 per cent share of total output. This is, however, lower than the 2012-13 figure of 18.5 per cent. Maharashtra has seen its share in total output declining from 17 per cent in 2012-13 to 13.8 per cent in 2019-20. Tamil Nadu has maintained its share at 10.3 per cent over the same period (see chart 3).

Gujarat is widening the output gap over Maharashtra

Shows share of total output (in %)



Data for top 5 states in terms of total output as of 2019-20

Source: Annual Survey of Industries, Business Standard calculations



India, historically, has had a strong regional concentration of industry. The share of the top five states in the 1959 Annual Survey of Industries showed Maharashtra accounting for 21.5 per cent of the capital expenditure in the year, and a similar share of workers directly employed. It was inevitable that this would come down as the years passed.

Gujarat’s ascendancy almost seems immune to the changes of time. Other states wooing industrial investors are likely to keep their fingers crossed.

-Sachin P. Mampatta,

Source: Business Standard, 10 Jun 2022

3.2 And Gautam Adani's wealth keeps growing too

Billionaire Industrialist Gautam Adani has edged past veteran investor Warren Buffett to become the world's fifth-richest person, according to data by Forbes. The sharp run-up in Adani Group stocks has led him to this feat. According to Forbes' Real-Time Billionaires List, Adani's wealth stood at \$123.7 billion as of Friday's close, racing past Buffett's \$121.7 billion, up from just \$8.7 billion in 2019. However, their Net Worth fell to \$99.9 Billion as on 28th Jun 2022.



Infrastructure tycoon Gautam Adani controls Mundra Port, India's largest, in his home state of Gujarat. His \$13 billion (revenue) Adani Group's interests span infrastructure, commodities, power generation and transmission and real estate. Adani acquired a 74% stake in Mumbai International Airport, India's second-busiest, in September 2020. He's now the country's biggest airport operator.

In May 2022, he made a big entry into cement when he won the race to acquire Swiss giant Holcim's cement business in India for \$10.5 billion. Adani wants to be the world's largest producer of green energy and has said he will invest upto \$70 billion on renewable energy projects.

The Economist

On his 60th birthday, Adani announced that the Adani family will donate Rs 60,000 crore; focus on health, education and skill development. In what is among the biggest charitable donations by an Indian corporate family, Gautam Adani and his family have pledged to donate Rs 60,000 crore that will be utilised in healthcare, education, and skill development, his logistics-to-energy conglomerate said in a statement. The donation will be managed by the Adani Foundation.

“To utilize the potential of India’s demographic advantage, there is an ever-growing need to focus on the areas of healthcare, education, and skill development,” the statement said. “The Adani Foundation has gained rich experience in working with communities focused on integrated development efforts across all these areas ... addressing these challenges can significantly enhance the competence and competitiveness of our future workforce,” it added.

(Sources: Forbes, The Economist, Economic Times and The Indian Express)



4 Environment, Natural Resources and Sustainability- Groundwater situation in Maharashtra

Yugandhar Mandavkar

4.1 Introduction

Use of surface water storages for irrigation has been an age old practice in India. After independence, India invested huge amounts on creating surface water and canal infrastructure. The ground water resources became a choice of farmers for irrigation through the construction of millions of private wells, resulting in a phenomenal growth in the exploitation of groundwater in the last six decades. Today, India is the largest groundwater user in the world, with an estimated usage of around 230 cubic kilometres per year, more than a quarter of the global total. With more than 60 percent of irrigated agriculture and 85 percent of drinking water supplies dependent on it, groundwater is a vital resource for rural areas in India (World Bank, 2010).

With increased access to knowledge, technology, finance and energy for the purpose of groundwater extraction, depletion of groundwater is a serious issue that has now turned into a water crisis in many parts of the country. The gap in demand and supply is continuously increasing, as also the numbers of critical and over exploited units are on rise. This mismanagement of natural wealth has serious social, economic and ecological consequences. In order to address the problem, one of the hindrances is the lack of data on the geological and hydrological characteristics and the health of the aquifers in different regions. The present study is an attempt to study the ground situation in some of the critical regions of India, with a view to provide guidance for sustainable groundwater management in India. The present assessment of groundwater situation in Maharashtra, which is presented in this note, has been taken up towards this end.

Groundwater has been the most preferred source of water for domestic use and irrigation in Maharashtra since 1970s. Changes in groundwater availability and quality impact human health, livelihoods, food security and economic development. Sustainable management of groundwater requires reliable estimates of its availability and dependability in terms of the timing, quantity or quality. This paper looks at the assessment of groundwater resources carried out in Maharashtra state over the last two decades.

The objective of the study is to develop an overview of the hydro-geological characterises of Maharashtra state and the extent of ground water extraction. It entails the study of the key characteristics of hydrology and hydrogeology of the state and the extent of groundwater availability on a sustainable extraction basis. It also looks at the state of groundwater extraction in the state at present and how has it changed over the years.

This note is based on a quick review of available reports and papers from official agencies and academics. It is written with a view to provide an overview of the situation of groundwater management in the state, and more importantly, to give a diagnostic view of the broad canvas on which the future strategies of groundwater management should be designed and developed.

The hydro-geological characteristics of the state were understood from the textbooks on geology and the finer aspects were understood from the academics and experts through discussions. Groundwater Survey and Development Agency (GSDA), which is the groundwater department of Government of India and Central Ground Water Board (CGWB) carried out periodic assessments in the state. Their reports were used to analyse the status of groundwater for this note. In addition, some research papers and articles on localised observations were used to corroborate the findings of the official assessment report.

4.1.1 Hydro-geology of Maharashtra

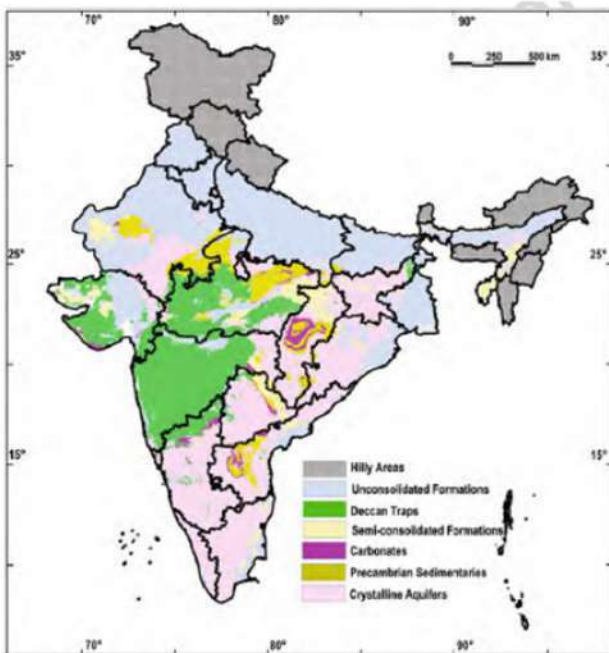


Fig 1 : Hydrogeological Map of India

Maharashtra, the third largest state in India has a total geographical area of 307,762 sq km, lies between latitudes of 15°45' and 22° 00' N and longitudes of 73° 00' and 80° 59' E in the west-central part of India (Fig 1). Maharashtra is divided in three main physiographic units the Sahyadri Range (Western Ghats), the Western Coastal Tract (Konkan), and The Eastern Plateau (Deccan Plateau). It is drained by Rivers Godavari, Krishna, Tapi, Mahanadi, Narmada and westward flowing rivers of Konkan; these constitute the six major river basins (Fig 2).

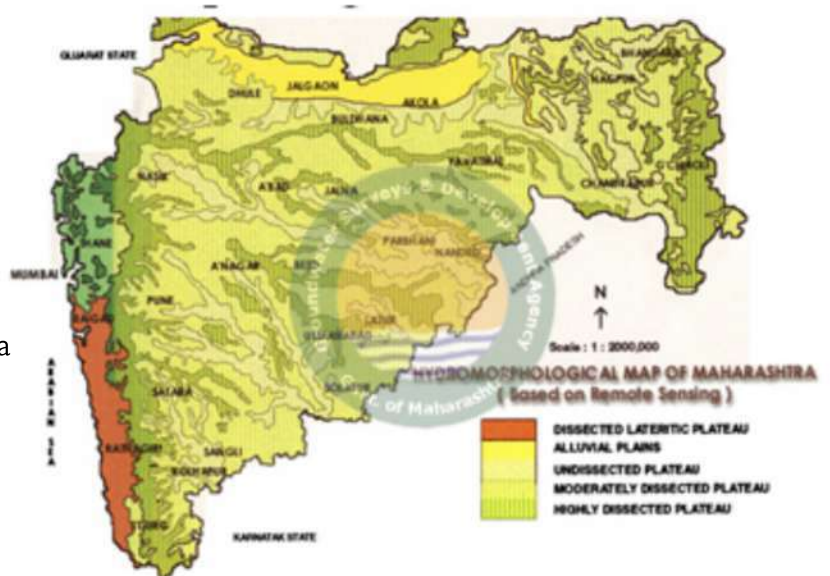


Fig 2:
Physiographic Map of Maharashtra

Maharashtra has five socio-cultural regions namely Konkan, Western Maharashtra, Khandesh, Marathwada and Vidarbha, which broadly match with the six administrative divisions namely Konkan, Pune, Nashik, Aurangabad, Amravati and Nagpur. These administrative divisions are divided into 36 districts. Further, the State can be divided into six distinct agro-climatic zones, each with its typical hydro-meteorological parameters. Thus, Maharashtra State has diverse physiography, hydrology and hydrogeology besides varying rainfall patterns. Physiography and geology have played a vital role in the availability of natural resources including water resources.

4.1.2 Geology of Maharashtra

Geology of Maharashtra State is practically the geology of Deccan Trap, which occur in all the districts of the State excepting Bhandara. The other geological formations, older and younger than Deccan Trap, occur in the districts of Bhandara, Wardha, Chandrapur, Gadchiroli, Nagpur, Yavatmal, Buldhana, Akola, Amravati, Dhule, Jalgaon, Nanded, Kolhapur, Sindhudurg and Ratnagiri. In the remaining 14 districts, Deccan Trap is the only geological formation occurring in them. These Deccan Traps are capped by laterites as seen in Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg, Satara, Sangali, Kolhapur and Osmanabad districts. The distribution of these formations is given in Table 1 and depicted in Fig 3 below.

Table 1 : Geology of Maharashtra

S No	Formation	Area, sq km	Percentage
1	Pleistocene and Quaternary Alluvial Sediment	14,500	4.71
2	Deccan Trap lava flows	2,50,000	81.20
3	Gondwana Sedimentary rock formation	4,800	1.55
4	Vindhyan and Cuddappah Pre-Cambrian sediments	6,200	2.00
5	Archean and Dharwad Metamorphic complexes	32,200	1.048

(Source : GSDA)

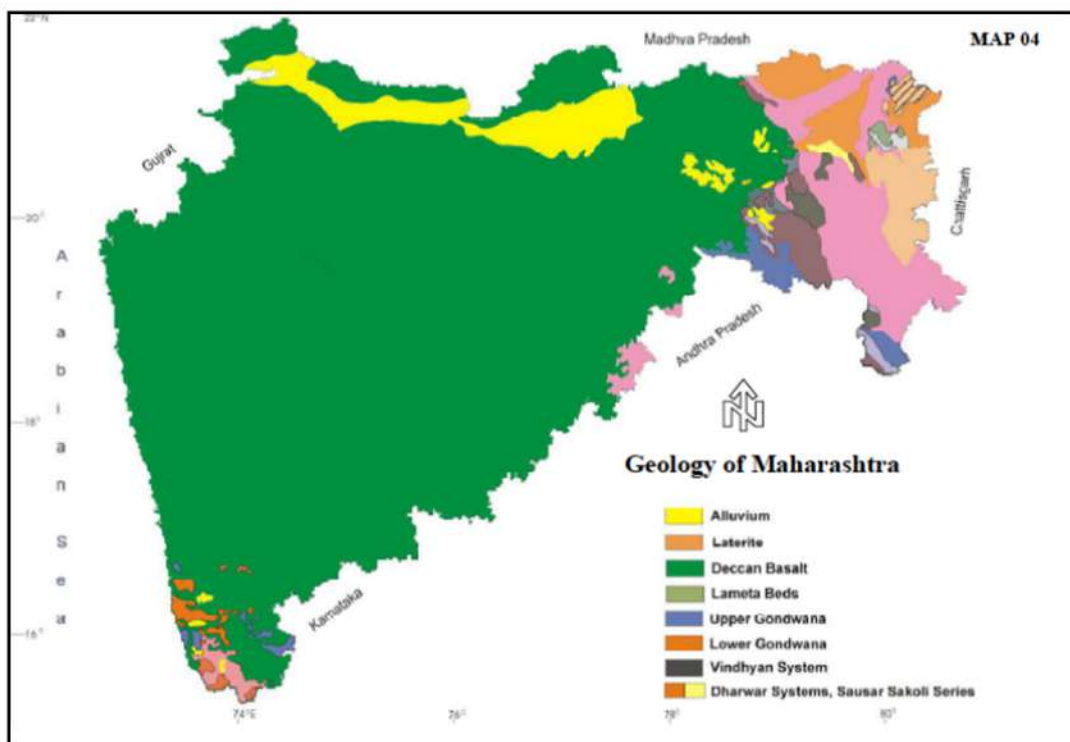


Fig 3. Geology of Maharashtra

4.2 Groundwater Assessment Methodology

Assessment of groundwater resources assumed importance as dependence on groundwater for drinking and domestic uses and irrigation started growing. In Maharashtra, groundwater exploration was started in 1973 soon after the formation of Groundwater Survey and Development Agency (GSDA) as the state groundwater department. A comprehensive groundwater resource assessment in Maharashtra was carried out in 1979. From 1987 onwards, it became almost a regular feature with an interval of about 3-4 years. The Central Ground Water Board (CGWB) started collaborating with these state level initiatives, and from the turn of the century started compiling the report at national level.

Methodology: While the first ad hoc attempt of estimating groundwater resources in Maharashtra was made during 1973, the first scientific assessment was carried out during 1979 on the basis of Overexploitation Committee Report published by Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC). Since then, various committees constituted by Government of India and Government of Maharashtra have suggested improvements in the methodology to estimate the groundwater resources. The estimations of 1987 and 1990 were carried out based on the methodology suggested by Groundwater Estimation Committee constituted in 1982 by Government of India (GEC-84), whereas that from 2000 to 2013 were carried out according to the guidelines of the Groundwater Estimation Committee 1997 (GEC-97). Subsequently, the guidelines were further modified in 2015 (GEC-15), which were used for assessment during 2017 and 2020 (Table 2).

Table 2 : Key characteristics of Groundwater Assessment Studies in Maharashtra

Details of assessment	1988	1990	2000	2004	2008	2011	2013	2017	2020
No of Watersheds	1,505	1,505	1,505	1,505	1,531	1,531	1,531	1,531	1,535
Methodology	GEC-84	GEC-84	GEC-97	GEC-97	GEC-97	GEC-97	GEC-97	GEC-15	GEC-15

(Source: Compiled by author from GSDA and CGWB data)

The state of Maharashtra has 35 districts and 353 talukas, out of which the two urban districts of Mumbai and Mumbai Suburban (erstwhile Bombay and Greater Bombay districts) were excluded from the assessment, thus covering the remaining 33 districts which are rural. Until 2004, the estimation was carried out for 29 districts before bifurcation, i.e., combined estimate for Parbhani-Hingoli, Dhule-Nandurbar, Bhandra-Gondia and Akola-Washim. Similarly, the 2004 assessment compiled the status based on 318 talukas before bifurcation.

For the purpose of groundwater estimation and evaluation, Maharashtra State was divided into 1535 elementary watersheds (This number was 1505 until 2004, 1531 from 2008 to 2013 and 1535 from 2017 onwards). The recharge was estimated for the groundwater worthy area of all the watersheds, while the non-worthy area comprising of steep slopes more than 20 per cent, hill tops and rocky wastelands have been left out. Each watershed was further delineated into poor groundwater quality area, where the quality of the groundwater was beyond the usable limits, as also into command and non-command area. In this fashion, each watershed was divided into three assessment subunits, but all the subunits may not be present in the single watershed. Hence, the assessment was carried out on a watershed basis, although initially the assessment was carried out for the command and non-command areas.

Classification: Until 1990, the status of groundwater situation was defined using the following terminology, as per the protocols of GEC-84. For working out the water balance, 70% of the gross extraction was taken as net draft. The rest 30% was presumed to go as return flow to the groundwater regime. The categories of watersheds were made on the basis of stage of development over a five year period (Table 3).

Table 3 : Categories of Watersheds (until 1990)

S No	Stage of Development	Category
1	Up to 65%	White
2	65% to < 85%	Grey
3	85% to < 100%	Dark
4	Over 100 %	Overexploited

From the assessment of 2004 onwards, the status of groundwater situation was defined using a new terminology, in line with the recommendation of GEC-97. The units of assessment are categorised for groundwater development based on two criteria, viz., stage of groundwater development, and long term trend (preferably, over a period of 10 years) of pre and post monsoon water levels. The assessment of 2011-12 was based on the guidelines issued in 2010 (first in January and subsequently revised in July 2010). The national level groundwater assessment of 2019-20 was carried out following the guidelines mentioned in the GEC-2015 methodology using appropriate assumptions depending on data availability. However, the Groundwater Yearbook of 2019-20 for Maharashtra is silent on the methodology.

Four categories were defined as safe, semi-critical, critical and over-exploited. In Semi-Critical areas, cautious groundwater development is recommended; whereas in Critical and Over-exploited areas, intensive monitoring and evaluation was recommended and water conservation measures along with any future ground water development. The criteria for categorisation of assessment units are as follows (Table 4).

Table 4 : Criteria of categorisation (After 2000)

S No	Stage of GW Development	Significant Long Term Decline		Category
		Pre-monsoon	Post-monsoon	
1	Up to 70%	No	No	SAFE
		Yes/No	No/Yes	To be re-assessed*
		Yes	Yes	To be re-assessed*
2	70% to 90%	No	No	SAFE
		Yes/No	No/Yes	SEMI CRITICAL
		Yes	Yes	To be re-assessed*
3	90% to 100%	No	No	To be re-assessed*
		Yes/No	No/Yes	SEMI CRITICAL
		Yes	Yes	CRITICAL
4	Over 100%	No	No	To be re-assessed*
		Yes/No	No/Yes	OVER EXPLOITED
		Yes	Yes	OVER EXPLOITED

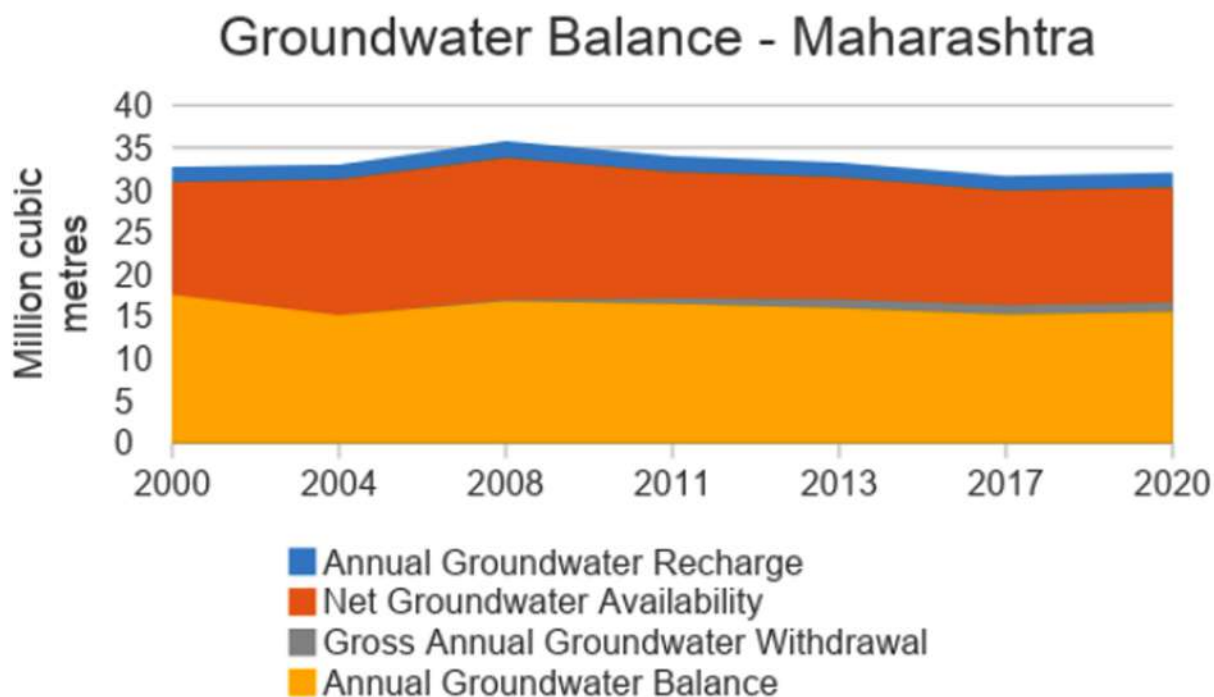
*Note : The term 'To be re-assessed' means that the computation should be reviewed and the reliability of the data used is to be checked for the purpose of categorisation.

Groundwater situation

The groundwater assessment, both recharge and draft, was carried out considering watershed as unit and within that command, non-command and poor quality zones as subunits. The final assessment of the potential is apportioned and presented as taluka wise. For the purpose of analysis, this study looked at the periodic assessments carried out from 1987-88 to 2019-20. However, data on similar variables was not available consistently for this period, and therefore, the trends from 2000 to 2020 were analysed for those variables for which data was available.

Groundwater availability: The total rechargeable groundwater resource has been around 30 billion cubic metres (BCM) to 35 BCM. However, a slight reduction (of around 5%) is expected on account of outflows or losses from the aquifer, and around 95% of it is available for abstraction as the net amount. The groundwater withdrawal has been varying from 13.33 BCM in the year 2000 to 17.18 BCM in year 2011 (Fig 5).

Fig 5 : Trends in dynamic groundwater resources



There has been a reduction in this figure during the last two assessments (16.33 BCM in 2017 and 16.63 BCM in 2020), which is due to change in methodology as per the GEC-15 guidelines, where the draft was calculated on the basis of the wells which were functional during the year. It was observed that the Gross Annual Withdrawal has been continuously increasing from 43.15% of the Net Groundwater Available in 2000 to 54.97% in 2020. The increase in draft has mainly been due to increase in number of irrigation wells (Table 5).

Fig 5 : Trends in dynamic groundwater resources

S No	Details of assessment	2000	2004	2008	2011	2013	2017	2020
1	Annual Groundwater Recharge	32.69	32.96	35.73	33.95	33.19	31.64	32.01
2	Net Groundwater Availability	30.89	31.21	33.81	32.15	31.48	29.90	30.25
	As % of Net availability	94.49	94.70	94.61	94.71	94.85	94.50	94.50
3	Gross Annual Groundwater Withdrawal	13.33	15.09	17.00	17.18	17.07	16.33	16.63
	As % of Net availability	43.15	48.34	50.29	53.42	54.22	54.62	54.97
4	Annual Groundwater Balance	17.56	15.13	16.81	16.45	15.93	15.19	15.54

(Source : Compiled by author from GSDA and CGWB data)

Categorisation: The categorisation of watersheds according to the severity of groundwater exploitation until 1990 is presented in the following table.

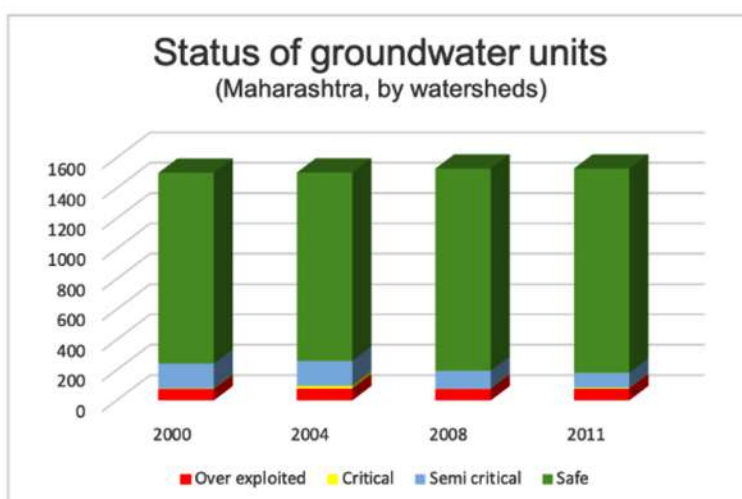
Table 6: Categories of Watersheds (until 1990)

S No	Category	Stage of Development	No of watersheds in 1987	No of watersheds in 1990
1	White	Up to 65%	1414	1392
2	Grey	65% to < 85%	57	87
3	Dark	85% to < 100%	34	26
4	Overexploited	Over 100 %	0	0

(Source: GSDA)

The names of the categories and method of categorisation changed from 2004 onwards as per the GEC guidelines. The observed trend is presented graphically in Fig 5 below.

Fig 5 : Categorisation of Watersheds



It may be noted that the watershed-wise data on the categories are not available from GSDA from 2013 onwards as these reports are not yet made public (Table 7a).

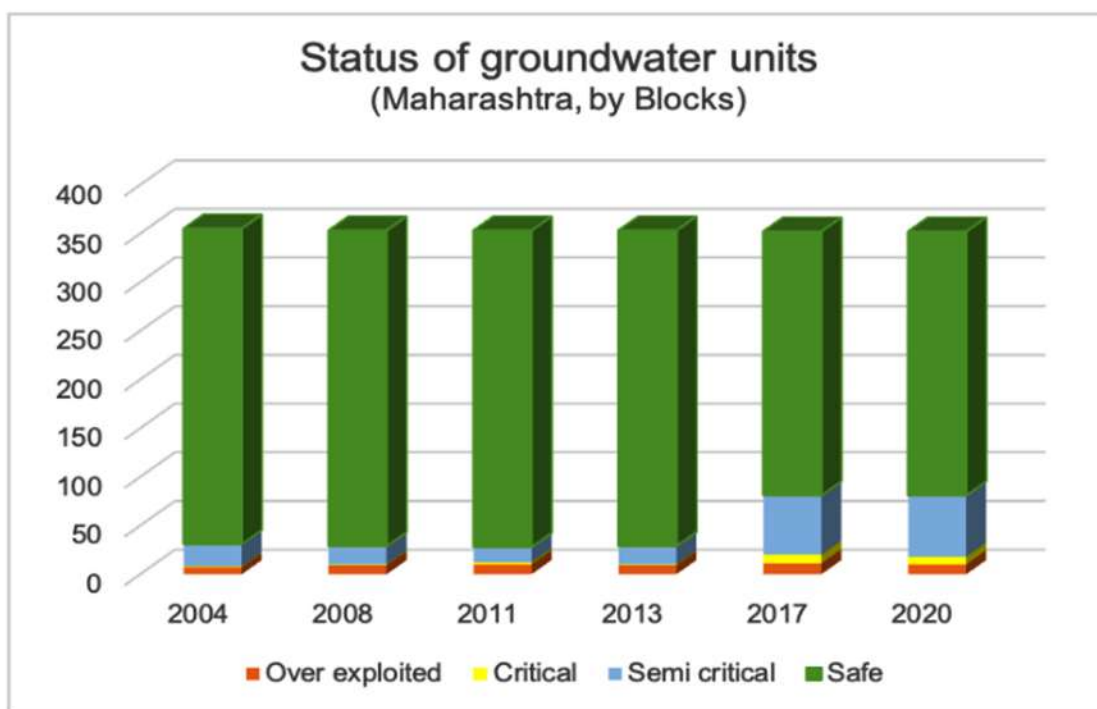
Table 7a: Watershed-wise Groundwater Status

Number of watersheds	2000	2004	2008	2011	2013	2017	2020
Over exploited	72	76	73	76			
Critical	6	20	3	4			
Semi critical	164	163	119	100			
Safe	1257	1242	1332	1347			

(Source : Compiled by author from GSDA and CGWB data)

The Central Ground Water Board compiles and published the data on the basis of administrative units like Tehsils, Talukas, Blocks, Mandals, etc. The trends in block-wise categorisation indicates that the proportion of unsafe blocks has been increasing over the years (Fig 6).

Fig 6 : Categorisation of Blocks (2000-2011)



While the trend does not prominently show any major changes in the over-exploited blocks, the rise in the critical and semi-critical blocks has been on the rise (Table 7b). Even if we tend to attribute the sudden jump in the number of such blocks from 2017 onwards due to change in methodology, the other parameters are indicative of the declining trend.

Table 7b: Block-wise Groundwater Status

Number of blocks	2004	2008	2011	2013	2017	2020
Over exploited	7	9	10	9	11	10
Critical	1	1	2	1	9	8
Semi critical	23	19	16	19	61	63
Safe	287	324	325	324	271	271

(Source: CGWB)

CGWB has also been publishing the changes in the categories of blocks, which corroborates the above observation on trends (Table 8). While the figure of 345 blocks out of 353 showing no change may be consoling, it has to be viewed in the overall context and other indicators.

Category	2011-2013	2013-2017	2017-2020
Improved	5	3	5
Deteriorated	5	63	3
No change	343	286	345

4.3 Discussion on current and future scenarios

4.3.1 Status and trends

Out of the total area under irrigation, groundwater accounts for 71%-75% across different years. Out of the total groundwater consumed, 85 per cent is for irrigation, 10 per cent is for industries and only 5 per cent is for domestic consumption. Drinking water needs of 90 per cent of the total rural population are entirely met from groundwater.

The groundwater balance, or the amount of groundwater available for abstraction for various uses, has been broadly around 15 BCM or 45%-55% of the net groundwater availability during the last two decades. Unfortunately, major part of it exists in the areas where development is not required for either irrigation or for drinking and/or is in areas, which are not favourable for development.

4.3.2 Potential and constraints

Groundwater availability depends on good rainfall in addition to the recharge from surface irrigation systems and soil water conservation measures, which replenished the groundwater in the non-monsoon period. On the other hand, the use in areas where well irrigation is common, the draft is often limited by the availability. Thus, higher monsoon rainfall leads to higher recharge, which further leads to increase in groundwater abstraction and use.

Identifying groundwater occurrence and assessing its availability in hard rock area are affected by the assessment geological formation and availability of reliable data. An example of the latter is the data on irrigation wells. After electrification of wells the numbers of irrigation wells with pumpsets are increasing continuously. As per the estimate of GSDA (2013), there were 10.07 lakh irrigation wells with pumpsets in the year 1988, which rose to 16.71 lakhs in the year 2007 and 21.07 in the year 2011.

It is a well-known fact that large number of irrigation borewells or tubewells are the main source of irrigation in all the parts of the State and large number of them are not on Revenue records or on electricity connections. The draft from those borewells or tubewells was the missing component from the assessment.

Groundwater occurrence is affected by the geological formation. Basaltic aquifers which occupy most part of Maharashtra comprise multiple flows (traps), each one being marked by a potential vesicular zone at the top and a massive rock unit underneath. The weathered part of the top flow and the vesicular zone of the successive flows below and the intertrappeans form aquifers. Groundwater occurs more in the cracks and fissures in these rocks. Locating and marking these flows and understanding their characteristics is a challenge and it affects the determination of aquifer expanse, which is the main factor in computing the volume of rechargeable groundwater.

Methodologies of assessment play important role in accurate and realistic estimation. Conventional approaches to understanding groundwater resources involve “geological provinces” or aquifer types can capture the gross physical characteristics of regional geological systems and the coverage of such systems. However, this classical approach, especially in the diverse context of India, not only simplifies the physical conditions that determine the storage, transmission and quality of groundwater, but remains only one-dimensional in failing to capture the anthropogenic dynamics that drive groundwater use.

The changes in suggested methodology from GEC-97 to GEV-2015 in the norms (threshold values for rainfall recharge, seepage from WCS, etc) marginal decrease in draft was observed during 2017 assessment, due to revision of well census data on the basis of functional wells. It led to the reduction in estimates of annual groundwater recharge from 33.19 to 31.64 BCM, annual extractable groundwater recharge from 31.48 to 29.90 BCM and annual ground water extraction from 17.07 to 16.33 BCM.

To summarise, while the overall trends do not show a serious decline in groundwater availability in the state as a whole, there are several areas facing scarcity. Further, the demand for groundwater is on the rise. All these issues have to be addressed through a slew of measures for both supply side management (augmentation and recharge) and demand side management (water budgeting, water use planning, optimising allocations and monitoring use). The legal and policy instruments and their operationalisations are likely to help in the process.

4.3.3 Bibliography

CGWB (2016); Groundwater Year Book of Maharashtra and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli (Water Year 2015-16); Nagpur, Central Ground Water Board, Central Region; September 2016

CGWB (2017); Groundwater Year Book of Maharashtra and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli (Water Year 2016-17); Nagpur, Central Ground Water Board, Central Region; October 2017

CGWB (2019); Groundwater Year Book of Maharashtra and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli (Water Year 2018-19); Nagpur, Central Ground Water Board, Central Region; December 2019

CGWB (2021); Groundwater Year Book of Maharashtra and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli (Water Year 2019-20); Nagpur, Central Ground Water Board, Central Region; January 2021

CGWB (2021a); National Compilation on Dynamic Ground Water Resources of India, 2020; Faridabad, Central Ground Water Board; June 2021

GSDA (2004); Report on the Dynamic Ground Water Resources of Maharashtra as on March 2004 by Groundwater Surveys and Development Agency (GSDA) and Central Ground Water Board (CGWB), Central Region, Nagpur; Pune, Groundwater Surveys and Development Agency (undated).

GSDA (2011); Report on the Dynamic Ground Water Resources of Maharashtra (2008-2009) by Groundwater Surveys and Development Agency (GSDA) and Central Ground Water Board (CGWB), Central Region, Nagpur; Pune, Groundwater Surveys and Development Agency; March 2011.

GSDA (2014); Report on the Dynamic Ground Water Resources of Maharashtra (2011-12) by Groundwater Surveys and Development Agency (GSDA) and Central Ground Water Board (CGWB), Central Region, Nagpur; Pune, Groundwater Surveys and Development Agency; February 2014

Jha, B. M and S K Sinha (2009); Towards Better Management of Ground Water Resources in India; J. Water and Energy International; 67(1).

Moench, Marcus, Ajaya Dixit, S. Janakarajan, M. S. Rathore and Srinivas Mudrakartha (20); The Fluid Mosaic : Water Governance in the Context of Variability, Uncertainty and Change; Kathmandu, Nepal, Nepal Water Conservation Foundation.

Suhag, Rupal (2016); Overview of Groundwater in India; PRS India; February 2016. Available at: https://prsindia.org/files/policy/policy_analytical_reports/1455682937--Overview%20of%20Ground%20Water%20in%20India_0.pdf (Accessed : 12 Feb 2022)

World Bank (2010); Deep Wells and Prudence : Towards Pragmatic Action for Addressing Groundwater Overexploitation in India; Washington DC, The World Bank



5 India's Place in the World- Focus on India-Russia talks (compilation from various sources)

5.1 PM Modi and Vladimir Putin hold comprehensive dialogue

PM Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin on Friday held comprehensive dialogue -- less than three days after G7 summit – to not only discuss Ukraine conflict but also reviewed implementation of the 2021 Annual Summit outcomes including in the field of defence and exchanged ideas to boost trade in agriculture, fertilisers and pharma products.

The leaders also discussed global issues, including the state of the international energy and food markets, officials said. In the context of the ongoing situation in Ukraine, Prime Minister reiterated India's long-standing position in favour of dialogue and diplomacy. The leaders agreed to maintain regular consultations on global and bilateral issues. “The two leaders reviewed the implementation of the decisions taken during President Putin's visit to India in December 2021. In particular, they exchanged ideas on how bilateral trade in agricultural goods, fertilizers and pharma products could be encouraged further,” according to a statement issued by the Prime Minister's Office. A 10-year defence agreement plan was signed during Putin's December 2021 visit for the annual Summit.



https://economictimes.indiatimes.com/news/india/pm-modi-and-vladimir-putin-hold-comprehensive-dialogue/articleshow/92605382.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

By Dipanjan Roy Chaudhury, The Economic Times, 2 July 2022

Earlier, Vladimir Putin's brief but important visit to India was watched by the world. Putin, who had not travelled much outside Russia during the pandemic, made the trip to Delhi, at a time when the pandemic was still raging in his country. He had only travelled to Geneva for the summit meeting with US President Joe Biden. This was his second visit outside Russia this year. India has a historical relationship with Russia, spanning over the last seven decades. While the relationship has stagnated in some areas and atrophied in some others, the strongest pillar of the strategic partnership is of the defence basket. Putin said: 'India great power, friendly nation, time-tested friend'. Echoing similar emotions, PM Modi said, "Despite the challenges posed by Covid-19, there is no change in the pace of growth of India-Russia relations. Our special and privileged strategic partnership continues to become stronger."

We reproduce below a commentary by Dr Rajeswari Pillai Rajagoplan of the ORF, which originally appeared in [The Diplomat](#).

5.2 Why Did Putin Visit India in Dec 2021?

Russian President Vladimir Putin visited India in the first week of December. The visit was significant in part because Putin has not traveled abroad to attend recent summits in person, like the G-20 in late October in Rome and COP26 in Glasgow, Scotland in November. Putin did go, however, to India for the 21st Annual India-Russia Summit with Indian Prime Minister Narendra Modi. The Russian president appears to have wanted to establish that Moscow can handle the India and China relationships independently of each other. Putin's visit is seen as an effort to repair the damage done to the relationship over the last couple of years, as Russia and India drifted apart.

Going by the optics and the number of memoranda of understanding (MoUs) and agreements signed by the two countries, Putin's India visit has attempted to bring back some balance in the relationship. A statement from the Indian Prime Minister's Office stated that the two leaders expressed "satisfaction at the sustained progress" in their bilateral relationship characterized as the "Special and Privileged Strategic Partnership." The two countries also held the inaugural round of a 2+2 Ministerial Dialogue involving the defence and foreign ministers of India and Russia. The Inter-Governmental Commission on Military & Military-Technical Cooperation also held a meeting during the visit.

A statement from the Indian Prime Minister's Office stated that the two leaders expressed "satisfaction at the sustained progress" in their bilateral relationship characterized as the "Special and Privileged Strategic Partnership."

Despite all the fanfare, it is not clear if India and Russia have managed to address the important contradictions in their bilateral relationship. The 99-point [joint statement](#) following the summit meeting highlighted a number of key areas for advancing bilateral cooperation in areas including civil nuclear and space, defence, transport and connectivity.

For Russia, China has become its go-to all-round strategic partner especially against the backdrop of Moscow's isolation from the West. But for India, China has become a primary threat, as the late Indian Chief of Defence Staff Gen. Bipin Rawat stated recently. This has necessitated that India develop closer strategic partnerships with the U.S. and others, like Australia and Japan, which share similar threat perceptions about China. This has created wrinkles in the India-Russia relationship, despite their close bilateral relations, as well as trilateral engagements such as the Russia-India-China (RIC) grouping and broader engagements such as through the BRICS and Shanghai Cooperation Organization (SCO). It is unclear if these India-Russia engagements will be sufficient to iron out the wrinkles that have come to the surface.

India-Russia differences in recent times over developments in the Indo-Pacific and China have become a significant limitation in India-Russia relations. That their annual summit meeting was cancelled in 2020 was a reflection of the difficulties facing their decades-old relationship. The Indian Ministry of External Affairs said that the summit was cancelled on account of the COVID-19 pandemic, but given that other international summits and meetings were being held virtually in 2020, the explanation for the complete cancellation was not entirely convincing.

India-Russia differences in recent times over developments in the Indo-Pacific and China have become a significant limitation in India-Russia relations.

Indeed, there was an Indian news report at the time which [said](#) that the summit did not take place due to “severe reservations [from Moscow] on New Delhi joining the Indo-Pacific initiative and Quad.” These difficulties in the relationship had come out in the open with Russian statements and Indian counter-statements. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has been quite open about his views on India’s Indo-Pacific policy and Quad engagement, as he was at the annual Raisina Dialogue in January 2020. Later in the year, he again stated at a general meeting of the Russian International Affairs Council in December that “India is currently an object of the Western countries’ persistent, aggressive and devious policy as they are trying to engage it in anti-China games by promoting Indo-Pacific strategies, the so-called ‘Quad’ while at the same time the West is attempting to undermine our close partnership and privileged relations with India.”

In reply to this statement, the usually cautious Indian Ministry of External Affairs responded by saying that India has always maintained an independent foreign policy, which is premised on its own national interests, and that India’s Indo-Pacific approach was not focused on any particular country. India also added that its foreign relations with a particular country stand independent of its relations with other countries, and that it must be understood as such.

While the political differences are one set of problems, the Russian sale of advanced weaponry and major defence platforms to China are another source of worry to India. Over the last few years, Russia has sold China advanced Kilo-class submarines as well as Su-35 fighter jets which could change the military balance in favour of China in significant ways.

Despite the fact that India has been trying to diversify its defence trade partners, Russia continues to be an important player, maintaining a dominance of about 70 percent of the Indian defence inventory.

Despite these challenges, during Putin’s visit India and Russia signed 28 MoUs on several different areas including cooperation on outer space, defence, and energy security involving government departments and commercial organizations of both countries. Among the agreements and MoUs signed during the visit was an existing agreement for the joint production of around 600,000 AK-203 assault rifles at a manufacturing facility in the north Indian state of Uttar Pradesh and an extended pact on military cooperation for 10 years from 2021 to 2031. Despite the fact that India has been trying to diversify its defence trade partners, Russia continues to be an important player, maintaining a dominance of about 70 percent of the Indian defence inventory.

That India went along with the S-400s from Russia, despite the threat of Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) sanctions, must have been welcoming to Putin and brought some reassurance about the endurance of the India-Russia relationship. Nevertheless, the contradictions in the relationship on account of the China factor may be difficult to overcome. These problems could become even more serious if the crisis in Ukraine further distances Russia from the West.



RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies

Jawahar Bhawan,
Dr Rajendra Prasad Road,
New Delhi 110 001
India

Please visit us at:

web: www.rgics.org



<https://www.facebook.com/rgics/>



<https://www.youtube.com/user/RGICSIndia>